● वर्ष-4
● अंक-52
रायपुर, मंगलवार
08 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6»»» गोभीवर्गीय में पोषक तत्वों की...

नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, नक्सली हिंसा पछले 10 साल में घटकर 7,700 रह गई

मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया होगा-शाह

नई दिल्ली/रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री शामिल हुईं। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्व में LWE प्रभावित सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और हमारे 8 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शाह ने कहा कि विकसित भारत का सही अर्थ है कि देश की 140 करोड़ की जनता तक विकास पहुंचे, जिनमें हमारे 8 करोड़ जनजातीय भाई-बहन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास को सही मायनों में दूरदराज़ के इलाकों और जनजातीय लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा आज नक्सलवाद है। नक्सलवाद गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और डाक सेवाएं आदि नहीं पहुंचने देता। श्री शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए हमें नक्सलवाद को समूल नष्ट करना होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2019 से 2024 तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि हम, केन्द्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से वामपंथी अंधकार की जगह संविधान प्रदत्त अधिकारों को जगह देना और वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास का एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। श्री शाह ने कहा कि हम वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत इंप्लीमेंटेशन से LWE-प्रभावित क्षेत्रों को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं।

अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए सरकार ने विधि के दो नियम तय किए थे। पहला, नक्सलवाद-प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित करना और गैरकानूनी हिंसक गतिविधियों को पूर्णतया बंद करना। दूसरा, लंबे नक्सली आंदोलन के कारण जो क्षेत्र विकास से महरूम रहे, वहां उस क्षति को तेज़ी से भरना। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 30 साल में पहली बार वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच नक्सलवाद की बहुत कम घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा, 14 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज़ किया गया और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का ग्राफ भी ऊपर चढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई आज अपने अंतिम चरण में है और मार्च, 2026 तक सभी के सहयोग से देश दशकों पुरानी इस समस्या से पूरी तरह मुक्ति पा लेगा। उन्होंने कहा कि आज बूढ़ा पहाड़ और चकरबंधा जैसे कई क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ख्ख्श्व की 85 प्रतिशत कॉडर स्ट्रैंथ समाप्त कर दी गई है और अब हमें नक्सलवाद पर एक अंतिम प्रहार करने की ज़रूरत है।

महाराष्ट्र इसमें रहेगा आगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। महाराष्ट्र इसमें आगे रहेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है कि कोई भी नई भर्ती नक्सल संगठनों में नहीं हो रही। जल्द महाराष्ट्र से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में पहले 550 नक्सल टीमें थी, अब सिर्फ 55-56 टीमें रह गई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बल अब नक्सलियों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई के बजाय आक्रामक अभियान चला रहे हैं और हाल के समय में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। शाह ने नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ। इससे पहले इस क्षेत्र में एक भी मत नहीं पड़ा था। इस महत्वपूर्ण बैठक में नक्सल-विरोधी अभियानों और प्रभावित क्षेत्रों में की गई विकास पहलों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम 31 नक्सलियों को मार गिराए जाने के कुछ दिनों बाद नक्सल-प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृहमंत्री की यह बैठक हुई है।

ओडिशा ने मांगे हेलीकॉप्टर

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य में माओवादियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से एक हेलीकॉप्टर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 12 कंपनियों की सोमवार को मांग की। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से माओवादियों के ओडिशा में प्रवेश की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि माझी ने सोमवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित माओवाद संबंधी समीक्षा बैठक के दौरान यह मांग उठाई। बयान में कहा गया कि माझी के साथ वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने सुरक्षा बल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व सैनिकों के ओएसएसएफ (ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स) की तीन बटालियन गठित की हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती किए गए कर्मियों को तैनात नहीं किया जाता, तब तक छत्तीसगढ़ से घुसपैठ को रोकने और खुफिया-आधारित अभियानों को बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में इस साल जनवरी से अब तक कुल 237 नक्सली मारे गए, 812 गिरफ्तार हुए और 723 ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट, कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 13 हज़ार से ज्यादा लोग हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। शाह ने कहा कि नक्सलवाद में लिप्त युवाओं से कहा कि सभी राज्यों ने उनके पुनर्वास के लिए हितकर योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से कभी किसी का फायदा नहीं होगा, ये बात अब पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में सरकार का फैसला आज

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 5 अक्टूबर को समाप्त हो गए। वोटों की गिनती कल 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे होगी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को हुआ था। जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर (24 सीटें), 25 (26 सीटें) और 1 अक्टूबर (40 सीटें) को तीन अलग-अलग चरणों में मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) हरियाणा में महत्वपूर्ण दल हैं। जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन किया है, जबकि इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन किया है।

हरियाणा- हरियाणा के चुनाव अधिकारी सितेंद्र सिवाच का ने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। आज रिहर्सल हो गई है। कल सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी। स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला है। इस चुनाव के परिणाम का इस्तेमाल विजेता द्वारा अन्य राज्यों में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया जाएगा, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। हरियाणा की 90 सीट पर 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं सहित कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं।

जम्मू और कश्मीर- जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और भाजपा जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण दल हैं। अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी), सज्जाद गनी लोन की जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (जेकेपीसी), और इंजीनियर राशिद की जम्मू-कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी अन्य महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रादेशिक मतदान केंद्रों की गिनती 25 स्थानों पर की जाएगी और प्रवासी मतदान केंद्रों की गिनती 3 स्थानों पर की जाएगी। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

रायपुर में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह युवाओं के लिए प्रेरणा का एक अद्वितीय स्त्रोत है। यह दिखाता है कि भारतीय सेना में शामिल होने का अर्थ केवल एक नौकरी पाना ही नहीं है बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पण की भावना से ओत-प्रोत होना है। **(विस्तृत समाचार पेज- 3 पर)**

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पूरे होने पर पीएम ने जताया आभार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे कर लिए हैं। आज के ही दिन 2001 में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफ की है। वहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी का आभार जताते हुए अपनी सार्वजनिक जीवन की यात्रा के बारे में बताया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को आश्वासन दिया कि वह और भी अधिक जोश के साथ अथक परिश्रम करते रहेंगे और तब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक कि विकसित भारत का सामूहिक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि इन 23 वर्षों में मिली सीख ने उन्हें अग्रणी पहल करने में सक्षम बनाया, जिसने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, एक सरकार के मुखिया के रूप में मेरे 23 साल पूरे होने पर अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों का हार्दिक आभार।

विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति

रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को दिल्ली में चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया। इस दौरान हर विधानसभा से तीन नामों का विकल्प रखा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वह राजग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर जल्द फैसला लेगी। बताया जाता है कि बैठक में भाजपा की झारखंड इकाई की ओर से संभावित उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए कम से कम तीन नाम सुझाए गए हैं। बैठक में सहयोगी दलों के साथ पार्टी के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। झारखंड में भाजपा, जद (यू) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) पार्टी के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है।

देश के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट से मुश्किल में घिरी कांग्रेस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए रुपए के ड्रग्स को बरामद किया गया है, जिसके बाद इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व युवा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भाजपा इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरने में लगी है। कांग्रेस से इसकी जवाबदेही मांगी जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ने 560 किलोग्राम कोकेन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना को साउथ दिल्ली से सीज किया था। इस पूरे मामले में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कनेक्शन सामने आ रहा है। इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमे तुषार गोयल अहम है, जिसे इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पूरे मामले में कांग्रेस को खुलकर घेरा है.

सिद्धारमैया 18 को पेश कर सकते हैं जाति जनगणना रिपोर्ट

नई दिल्ली। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में आखिरकार कुछ गति देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को घोषणा की कि वह इसे 18 अक्टूबर को कैबिनेट के सामने ला सकते हैं, क्योंकि उन पर ओबीसी समुदायों के विधायकों का भारी दबाव था और उन्होंने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया था। इससे पहले दिन में, सीएम ने विधान सौध में मंत्रियों, विधायकों और ओबीसी समुदायों के नेताओं के साथ बैठक की। सीएम ने मीडियाकर्मियों से कहा, ये नेता अपनी पार्टी लाइनों से ऊपर उठे और रिपोर्ट को लागू करना चाहते थे। प्रमुख समुदायों की ओर से आ रहे विरोध पर सीएम ने कहा कि वह कैबिनेट की सलाह मानेंगे। राज्य के स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले फरवरी में 13-खंड की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रिपोर्ट सीएम को सौंपी थी। हालाँकि, सरकार ने रिपोर्ट की सामग्री को गुप्त रखा है। सीएम ने कहा कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है। एच कंथाराजू आयोग ने सीएम के रूप में अपने पहले कार्यकाल (2013-2018) के दौरान घरों का दौरा करके सर्वेक्षण किया.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर सावधानी से नजर रख रहा भारत

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी पर भारत सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है। भारत को विश्वास है कि वह इस मामले में किसी भी चुनौती से निपट लेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को यह भरोसा जताया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 78 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। बाजार की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस्राइल पिछले सप्ताह ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले का जवाब देगा? पुरी ने नई दिल्ली में एक्सॉनमोबिल ग्लोबल आउटलुक 2024 में कहा, हम स्थिति पर बहुत सावधानी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। लेकिन आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश भारत किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम होने के प्रति आश्वस्त है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हम पहले की तरह ही आगे बढ़ सकेंगे। पुरी ने कहा कि तेल की कोई कमी नहीं है और भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के प्रति आश्वस्त है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस्राइल ईरान में तेल या परमाणु सुविधाओं को निशाना बना सकता है।

चिकित्सा के नोबेल का एलान; माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एंब्रोस-गैरी रुवकुन को चुना गया

साल 2024 के नोबेल पुरस्कारों का एलान सोमवार से शुरू हो गया। इसके तहत आज फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र के लिए इस सम्मान के विजेताओं के नाम का एलान किया गया। इस साल अमेरिका के विक्टर एंब्रोस और गैरी रुवकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले साल यानी 2023 में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया था। इस खोज की वजह से कोरोनावायरस यानी सीओवीआईडी-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास में मदद मिली थी। विक्टर एम्ब्रोस ने सी. एलिगेंस में विकासात्मक समय के जेनेटिक कंट्रोल को लेकर शोध किया है। यह खोज जीवों के विकास और कार्य करने के तरीके को समझने के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रही है। भले ही हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में एक जैसे जीन होते हैं, लेकिन मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं जैसी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग-अलग कार्य करती हैं। यह जीन विनियमन के कारण संभव है, जो कोशिकाओं को केवल उन जीनों को फ्रचालूफ्र करने की अनुमति देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। माइक्रोआरएनए को लेकर एम्ब्रोस और रुवकुन की खोज ने इस विनियमन के होने का एक नया तरीका बताया है।

एम्ब्रोस वर्तमान में मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। रुवकुन का शोध मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में किया गया था, जहां वह आनुवंशिकी के प्रोफेसर हैं।

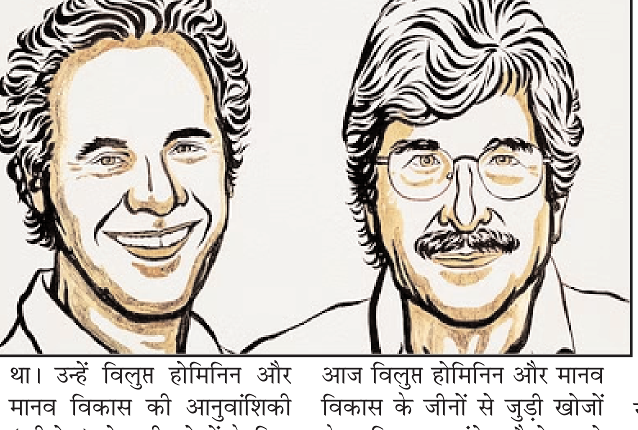

2022 में स्वीडन के स्वांते पैबो को मिला था पुरस्कार

2022 में स्वीडन के स्वांते पैबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवांशिकी (जीनोम) से जुड़ी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नोबेल समिति ने बयान जारी कर कहा था कि कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल समिति ने आज विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनों से जुड़ी खोजों के लिए स्वांते पैबो को फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया। स्वांते पैबो ने अपने शोध में पाया था कि विलुप्त होमोनिन जीन होमो सेपियन्स में ट्रांसफर हुए थे। पैबो पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक रहे हैं जिन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। वह जर्मनी के लीपजिंग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी मेंजेनेटिक्स विभाग के निदेशक भी रहे हैं।

2021 में इन वैज्ञानिकों को मिला था ये पुरस्कार

2021 का चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से डेविड जूलियस और आर्डेन पैटामूटियम को सम्मानित किया गया था। इन दोनों शोधकर्ताओं को शरीर के तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। दोनों नोबेल विजेता अमेरिकी थे। डेविड जूलियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे। वहीं पैटापूटियन अर्मेनियाई मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और ला जोला के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक थे।

आज से ही हुई शुरुआत

चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरूआत हो गई है। अब मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा 14 अक्तूबर को की जाएगी।

इतना मिलता है पुरस्कार

पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी एक मिलियन अमेरिकी डॉलर या दस लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवॉर्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार अधिकतम तीन विजेताओं को दिया जा सकता है। उन्हें पुरस्कार राशि साझा करनी होती है।

रिखी ने 108 लोक वाद्यों के साथ दी सामूहिक प्रस्तुति, मुख्यमंत्री साय ने सराहा

भिलाई। गैर सरकारी पहल 'लोकमंथन' की ओर से छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट का आयोजन 3 से 5 अक्टूबर तक राजधानी रायपुर में किया गया। इस दौरान इस्पात नगरी भिलाई निवासी व प्रख्यात लोकवाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं उन्होंने अपने संग्रहित लोकवाद्यों की प्रदर्शनी लगाई। जिसे देखने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित देश भर के कला संस्कृति से जुड़े लोगों भरपूर तारीफ की।

इस दौरान रिखी क्षत्रिय की कला व उनके वाद्ययंत्रों का संग्रह देख कर प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंदकुमार मुक्त कंठ से सराहना की और अगले माह हैदराबाद में 21 से 24 नवंबर तक होने वाले 'लोकमंथन' के चौथे संस्करण में शामिल होने का न्यौता भी दे दिया। वहां रिखी देश भर के आदिवासी लोक कला मर्मज्ञों और आदिवासी समुदाय के कलाकारों के बीच अपना संग्रह प्रस्तुत करेंगे और अपने समूह के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे।

रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम का समापन शनिवार 5 अक्टूबर को हुआ। यहां रिखी क्षत्रिय का लोक वाद्य संग्रह देखने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप चूंकि रिखी के संग्रह से पहले से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने यहां रखे ज्यादातर वाद्य यंत्रों का परिचय खुद होकर मुख्यमंत्री साय को दिया। इस दौरान रिखी क्षत्रिय ने घुमरा बाजा से शेर की आवाज निकाल कर दिखाई तो मुख्यमंत्री साय सहित सभी अतिथि हैरान रह गए। इसी तरह रिखी क्षत्रिय ने कुहुकी, चरहे, तोडी,

सिसरी,चिकारा,भेर और हुलकी आदि वाद्य भी बजाकर दिखाए। अतिथियों ने रिखी की इस प्रस्तुति की मुक्त कंठ से सराहना की।

रिखी ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री साय को तंबूरा भेंट किया। इस आयोजन में डॉ. एनवी रमण राव निदेशक एनआईटी रायपुर, प्रो. राजीव प्रकाश निदेशक आईआईटी भिलाई, प्रो. पीयूष कांत पांडे कुलपति एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, गोपाल आर्य अखिल भारतीय संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, वी. श्रीनिवास राव आई.एफ.एस. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, विनय दीक्षित फील्ड समन्वयक प्रज्ञा प्रवाह, प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और शंखदीप चौधरी अध्यक्ष, बिबग्योर एनई फाउंडेशन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

मोहरी की धुन लाइव बजती रही, भित्ती चित्र की लाइव पेंटिंग भी- यह आयोजन पूरी तरह आदिवासी लोक कला व संस्कृति को समर्पित था। यहां मंचीय प्रस्तुति के दौरान रिखी क्षत्रिय ने अपने 108 वाद्य यंत्रों के साथ अद्भुत कार्यक्रम दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ परब, बैगा करमा, गौर माड़िया और माड़ी करमा की प्रस्तुति दी। आयोजन स्थल में रिखी द्वारा संग्रहित मोहरी की धुन लाइव प्रस्तुत की जा रही थी वहीं बांस, रुंझु देवार और चिकारा की धुन सुन कर भी लोग चकित रह गए।

यहां आदिवासी समुदाय के भित्ति चित्र बनाने का लाइव प्रस्तुतिकरण शशि प्रिया क्षत्रिय उपाध्याय ने किया। पारंपरिक गोदना शैली का प्रदर्शन यहां किया गया। रिखी के समूह में नृत्य पक्ष में पारस रजक,प्रदीप ठाकुर, संजीव कुमार बैस, भीमेश,प्रमोद ठाकुर,सुनील कुमार,वेदप्रकाश देवांगन, रंजीत ठाकुर,वेन कुमार,नवीन साहू,नेहा विश्वकर्मा,जया ठाकुर,जागेश्वरी यादव,शशि साहू, लीना ध्रुव, हेमा डोंडे, प्रियंका साहू, सीमा, तुलेश्वरी डोंडे, रामकुमार पाटिल, कमल पटेल, राजेश, अजीत, गीतांजलि, दिनेश वर्मा और उग्रसेन का योगदान रहा।

महंत दंपत्ति ने देवी मन्दिरों में की पूजा-अर्चना

कोरबा। प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत और उनके पुत्र सूरज महंत ने रविवार को देवी मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन-अर्चन कर क्षेत्र-प्रदेश की जनता की खुशहाली और उन्नति की कामना की। अपने दो दिवसीय प्रवास पर मां दंपति ने रतनपुर

महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पाली ब्लॉक के ग्राम लाफा स्थित प्राचीन महामाया-काली मंदिर पहुंचकर पूजा आराधना किया। वहां पर उपस्थित महिलाओं, ग्रामीण और कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की और उनकी मांग पर दो स्थल पर चबूतरा निर्माण की घोषणा की। तत्पश्चात वे चैतुरगढ़ स्थित आदि शक्ति मां महिषासुर मर्दिनी के दरबार पहुंचे। माता के दरबार में माथा टेका। विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन आरती करने के पश्चात भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया।

मंदिर परिसर में प्रज्वलित सैकड़ो की संख्या में आस्था के दीपों के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचे दर्शनार्थियों से भी उन्होंने भेंट की। धार्मिक एवं जनकल्याण ट्रस्ट के पदाधिकारी ने उनका स्वागत और सम्मान किया। उनकी मांग पर सांसद श्रीमती महंत ने 35 लाख के विकास कार्यों की अनुशंसा भी की. इसके बाद वे पाली महामाया देवालय पहुंचे. जहां बैगा ने विधि विधान से पूजा कराई.यहां भी मंदिर समिति ने इनका आत्मीय स्वागत किया. महंत दंपति ने विकास कार्यों के लिए यहथासंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया. चैतमा में महामाया देवी मंदिर में माता के दर्शन के पश्चात कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात की. कुशल क्षेम पूछा और उनकी मांगों पर यथोचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया.इस दौरान पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा, सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा, हरीश परसाई, यशवंत लाल, राम नारायण कश्यप,त्रिलोक श्रीवास, सुरेश गुप्ता, अमित भदौरिया, अनिल गुप्ता, दीपक जायसवाल,सत्यनारायण पैकरा,रजेश गुप्ता,सत्य नारायण श्रीवास, पुनीराम पटेल, सावित्री श्रीवास,मुन्ना दास,सुमन आदि अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

माओवादियों से लोहा लेने वाले जांबाज जवानों से हुए रूबरू उपमुख्यमंत्री शर्मा

दंतेवाड़ा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि एवं आदि विकास मंत्री रामविचार नेताम एवं वनमंत्री केदार कश्यप आज दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा के कारली स्थित रक्षित केन्द्र के कॉम्प्लेक्स हॉल में उप मुख्यमंत्री शर्मा एवं मंत्रीद्वय ने सुरक्षा बलों के जांबाज जवानों से मुलाकात की और उनके साहसिक और सफल ऑपरेशन की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया।

गौरतलब है कि बीते 04 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नेन्दूर व थुलथुली में माओवादियों के विरूद्ध सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों से हुई मुठभेड़ में अपने अदम्य साहस से 31 माओवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में पुलिस बलों द्वारा डीकेएसजेडसी, डीवीसी, पीएलजीए कंपनी नंबर 6 के कई कैडर सहित 18 पुरुष एवं 13 महिला कुल 31 सशस्त्र वर्दीधारी माओवादी को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। मारे गए माओवादियों में 25 लाख का इनामी डीकेएसजेडसी एवं पूर्वी बस्तर इंचार्ज नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल थी।

मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में से अब तक हुई 15 शिनाख्तगी में

डीकेएसजेडसी के अलावा दो कैडर 8 लाख इनामी डीबीसीएम एवं 9 कैडर पीएलजीए, कंपनी 6 माओवादियों भी शामिल है। इस घटना में 01 नग एलएमजी, 04 नग एके 47, 06 नग एसएलआर, 03 नग इन्सास, 2 नग श्री नॉट श्री सहित अन्य हथियार बरामद हुए।

पुलिस बल के जवानों की टीम दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन, पीएलजीए कंपनी 6, इंद्रावती एरिया कमेटी, प्लाटून 16 इत्यादि के शीर्ष नक्सलियों के आने की सूचना के आधार पर सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले थे। इस संयुक्त टीम में दंतेवाड़ा डीआरजी, नारायणपुर डीआरजी और एसटीएफ शामिल थे। भारी बरसात में उफनते नदी नालों और माड़ की पहाड़ियों को पार कर पुलिस जवानों की टीम नक्सलियों के जमा होने वाले इलाके में पहुंची, और यहां हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इस बड़े ऑपरेशन में एक मात्र जवान घायल जवान के अलावा अन्य सभी जवान सुरक्षित रहे। इस अवसर पर पुलिस बल नेतृत्व कर रहे एडिशनल एसपी स्मृतिक राजनाला पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर सभी जवानों को बधाई देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर सभी जवानों के लिए शुभकामना संदेश लेकर आया हूँ, आपके अदभुत पराक्रम और शौर्य से बस्तर में सुख-शांति फिर से लौटेगी। इस अभियान से आपने देश और दुनिया की सोच बदली है, और मां दंतेश्वरी की कृपा इस भीषण मुठभेड़ में किसी भी जवान को कोई हानि नहीं हुई। बस्तर शांति का टापू रहा है, परन्तु कुछ दिग्भ्रमित लोगों के कारण यह की शांति भंग हुई है। हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के जवान ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करके ही रहेंगे। यह छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम मिले है। कृषि एवं आदिवासी विकास विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम इस सफल ऑपरेशन को विजय दिवस की संज्ञा देते हुए, कहा कि इस सफलता से पूरा देश गौरवान्वित है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इस सफल ऑपरेशन की चर्चा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलें में है। इससे माओवाद मुक्त बस्तर अभियान को एक नयी गति मिली है। इसके लिए सुरक्षा बलों सहित आईजी, डीआईजी तथा कलेक्टर, एसपी सभी बधाई के पात्र है। इस अवसर पर विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर सहित बस्तर आईजी सुंदरराज पी,डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, डीएफओ सागर जाधव, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके.बर्मन सहित अन्य पुलिस बल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

वन्य जीवों के रहवास के लिए छग के वन क्षेत्र सबसे उपयुक्तः कश्यप

नया रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग 2-8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे ''सह

अस्तित्व से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह'' थीम पर आधारित वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने का कार्यक्रम आज वन विभाग द्वारा ट्रिपल आईटी रायपुर के सभागार में आयोजित हुआ।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री श्री कश्यप ने इस मौके पर वन्य जीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की सुश्री रागिनी ध्रुव को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी।

सुश्री रागिनी ध्रुव अचानक मार्ग टायगर रिजर्व वन क्षेत्र के गांव शिवतराई की रहने वाली हैं। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु और भौगोलिक स्थिति अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर है। हमारा राज्य बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पांच दिन से लापता मासूम का शव बरामद, इलाके में हड़कंप

बलरामपुर। वाड्रफनगर ब्लॉक के तोरफा गांव में घर के सामने से रहस्यमय तरीके से गायब हुए 10 वर्षीय मासूम का शव पांचवें दिन मिला है। बच्चे का शव घर से करीब 500 मीटर दूर पर नदी किनारे सिर कटा हुआ बरामद हुआ है। बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला बलंगी पुलिस चौकी का है। वहीं इस मामले में ग्रामीण नरबलि की आशंका जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार, बलरामपुर के तोरफा गांव में पांच दिन पहले एक 10 वर्षीय बालक अपने घर के सामने से अचानक गायब हो गया था। जिसकी खोजबीन परिजनों ने आस-पास के इलाकों में की. लेकिन बच्चा नहीं मिला. जिसके बाद मामले की शिकायत परिजनों ने बलंगी पुलिस चौकी में की. शिकायत मिलते ही पुलिस मामले में जुट गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं आज सुबह बच्चे का शव घर से करीब 500 मीटर दूर पर नदी किनारे मिला है. बच्चे का सिर काटा हुआ शव बरामद किया गया है।

ट्रक की टक्कर से बाइक चालक की मौत

तुमगांव। तुमगांव थाना अंतर्गत कोडार चौक के पास एक मोटरसायकल चालक को ट्रक चालक द्वारा पीछे से ठोकर मारने पर गंभीर चोट लगने से मोटरसायकल चालक की मौत हो गई, जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 को चमरू खैरवार पिता नेटो खैरवार उम्र 46 साल, ग्राम रूमेकेल निवासी अपनी मोटर सायकल क्रमांक CG06GS5438 में बिरबिरा से अपने समधी के घर ग्राम पलसापाली जा रहा था. इसी दौरान शाम करीब 07.20 बजे कोडार चौक NH53 रोड के पास ट्रक क्रं0 MH41AU4567 का चालक ने अपने ट्रक को तेज लापरवाही पूर्वक चलाकर चमरू को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । जिससे मोटर सायकल चालक चमरू खैरवार का सिर, बांया पैर, बांया हांथ में गंभीर चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई तथा मोटर सायकल भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिस पर पुलिस ने आरोपी ट्रक क्रं0 MH41AU4567 का चालक का कृत्य अपराध धारा 106(1), BNS का पाय जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

नायब तहसीलदार बनाने के नाम पर 29 लाख का ठगी

भिलाई। नायब तहसीलदार बनाने के नाम पर पति पत्नी ने मिलकर एक किसान को ठग लिया। उन्होंने उससे 29 लाख रुपए तो लिया, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। जब उनकी नौकरी नहीं लगी तो किसान ने इसकी शिकायत दुर्ग कोतवाली थाने में दर्ज कराई। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम मोहलाई दुर्ग निवासी किसान नोखेलाल सिन्हा ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि वो किसानी के साथ-साथ सीजी पीएससी की तैयारी करता है। मोहंदी निवासी रेखराज खेलवार और उसकी पत्नी भारती खेलवार ने उसके साथ 29 लाख रुपए की ठगी की है। उन्होंने नोखेलाल को सीजी पीएससी के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया। इसके बाद 29 लाख 50 हजार रुपए लेकर चयन नहीं कराया। जब नोखेलाल का चयन नहीं हुआ तो उसने अपने रुपए उनसे मांगे।

बस्तर के एमए पाठ्यक्रम में पारकर का उपन्यास शामिल

भिलाई। शासकीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के बाद अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में भी आंचलिक साहित्यकार दुर्गा प्रसाद पारकर लिखित छत्तीसगढ़ी उपन्यास 'बहू हाथ के पानी' को विद्यार्थी पढ़ेंगे। इसके अलावा पारकर के रचनात्मक अवदान पर हाल ही में एक शोधार्थी ने अपनी पीएचडी पूरी की है। पारकर ने बताया कि उन्हें शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की ओर से जानकारी भेजी गई है कि एम ए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम 'जनपदीय भाषा और छत्तीसगढ़ी साहित्य' में इस साल दूसरे सेमेस्टर से उनका लिखा छत्तीसगढ़ी उपन्यास 'बहू हाथ के पानी' पढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। इसी तरह दुर्ग विश्वविद्यालय में 8 वें सेमेस्टर में उनका यह उपन्यास शामिल किया गया है। एक अन्य जानकारी में उन्होंने बताया कि कलिंगा विश्वविद्यालय कला एवं मानविकी विभाग ने गणेश राम कौशिक को उनके शोध कार्य पर पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की है।

जनपद अध्यक्ष सहित 6 सदस्य भाजपा में शामिल

सक्ती। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है. सक्ती जिले के जैजैपुर में जनपद अध्यक्ष रोशनी चंद्रा सहित 6 जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं. जिला अध्यक्ष के के चंद्रा ने सभी नए सदस्यों को भाजपा में शामिल कराते हुए उनका स्वागत किया. भाजपा प्रवेश करने वाले जनप्रतिनिधियों में जनपद अध्यक्ष रोशनी चंद्रा के अलावा किशन साहू, नारायण निराला, रंभा भारद्वाज, अंजनी सिदार, कृष्ण कुमार चंद्रा और राधे श्याम चंद्रा शामिल हैं.

डॉक्टर मरीजों के लिए देवता के समान : रूपसाय सलाम

▪ निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर में 1819 मरीजों का किया गया निःशुल्क उपचार

नारायणपुर। बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय में दो दिवसीय निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर मरीजों के लिए देवता के समान हैं, जो मरीजों को रोग से निजाद दिलाते हैं। उन्होंने मंशा जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र ओरछा और सोनपुर में मेगा चिकित्सा शिविर लगाकर उपचार कराने की अपील जिला प्रशासन से की है। उन्होंने चिकित्सों की कार्य को सराहना करते हुए कहा कि अबुझमाड़ क्षेत्र में आकर मरीजों का इलाज कर उनकी रोग से बचाव करने का कार्य किये हैं जो अमुल्य योगदान है।

कार्यक्रम को कलेक्टर बिपिन मांझी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंबेडकर चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सों के द्वारा दो दिवसीय शिविर में अबुझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों को निःशुल्क उपचार कर रोग से बचाव हेतु सराहनीय कार्य किया गया, जिसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भविष्य में शिविर की आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों की सेवा की पुनः जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सभी चिकित्सों को दो दिवसीय इलाज में सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी चिकित्सकों को दो दिवसीय शिविर में सहयोग देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि के हाथों प्रदान किया गया।

जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा भी मरीजों का उपचार करने में सहयोग करने के लिए उन्हें भी स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान सम्मानित किया गया। मेगा चिकित्सा शिविर में चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. के.के. साहू, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक अग्रवाल, डेंटल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता एवं डॉ. जितेंद्र सर्राफ, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद भीमसरिया, आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. श्रीनिवास एवं डॉ. प्रशांत रावत, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉ. संध्या एवं डॉ. चंदन अग्रवाल, दर्द एवं उष्माशक विशेषज्ञ डॉ. बबलेश महावर एवं डॉ. आशीष सिन्हा और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. आनंद बंसल तथा डॉ. संतोष भारद्वाज द्वारा पंजीयन करये मरीजों का उपचार किया गया। हड्डी रोग के 122, नेत्र रोग के 232, किडनी समस्या के एक, लिवर समस्या के 02, दंत एवं मुख रोग के 62, चर्म रोग के 63, कान नाक एवं गला रोग के 65, हृदय रोग के 30, स्त्री रोग के 15, शिशु रोग के 47, न्यूरोलॉजी रोग के 16, मानसिक रोग के 46 और सर्दी खासी और बुखार के 1118 के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया।

गाली-गलौज कर रहे बदमाश को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा, मौके पर हुई मौत, 26 लोग हिरासत में

दुर्ग। भिलाई के हथखोज शीतला पारा में कल देर रात एक आदतन बदमाश की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतक के खिलाफ पुरानी भिलाई थाने में कई मामले दर्ज थे और वह हाल ही में जेल से छूटकर आया था. यह मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, मृतक आशिक विश्वकर्मा कल रात अपने 7-8 दोस्तों के साथ हथखोज पहुंचा और ग्रामीणों से गाली-गलौज करने लगा. ग्रामीणों ने पहले उसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब वह अभद्रता करने लगा, तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया और उसके गैंग पर हमला कर दिया. वहीं मौके पर मौजूद

उसके साथी भाग खड़े हुए, जबकि ग्रामीणों ने आशिक को दबोच लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुरानी भिलाई पुलिस ने मौके ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है. वहीं ,मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर रात से सुबह तक कुल 26 लोगों को हिरासत में लिस के अनुसार आशिक आदतन बदमाश था. उसके खिलाफ पुरानी भिलाई थाने में कई शिकायत दर्ज हैं. पिछले महीने जरवाय में हुई एक घटना के बाद पुलिस ने आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस संगठित अपराध के मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए जांच कर रही है. फिलहाल हथखोज में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है.

संक्षिप्त समाचार

6 जिलों में 8 सड़कों के विकास के लिए 892.36 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत दी गई है। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य के 6 जिलों में 8 सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह परियोजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति देंगी और जनता के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी।

मनीषा यदु को पीएचडी की उपाधि

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र व समाजकार्य अध्ययनशाला ने मनीषा यदु को पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने अपना शोध कार्य सामाजिक विकास में महिला स्वैच्छिक संगठन की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रीमती हेमलता बोरकर वासनिक के निर्देशन में पूर्ण किया है। इनके द्वारा महिलाओं के समाज में योगदान संबंधित विभिन्न शोध पत्र राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान शोध महिलाओं के विषय में शासकीय नीतियां बनाने में सहयोगी होगा। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गुरुजनों मित्रों व परिवारजनों ने बधाई दी है।

अपूर्वा को ग्रीन समिट सम्मान

रायपुर । तीन दिवसीय राष्ट्रीय ग्रीन समिट के तकनीकी सत्र में बस्तर की बेटी, अपूर्वा त्रिपाठी ने बस्तर में जैविक पद्धति से की जा रही लाभदायक बहुस्तरीय खेती के अंतर्गत जड़ी बूटियों की खेती तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए नेचुरल ग्रीनहाउस मॉडल पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि नेचुरल ग्रीनहाउस न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का भी एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। यह मॉडल प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला साबित हो रहा है। अपूर्वा, कानून विशेषज्ञ होने के साथ-साथ वनवासी महिलाओं के अधिकारों पर शोध कर रही हैं, जिन्होंने दुर्लभ और औषधीय पौधों की खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। अपने कार्य अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एवं रिसर्च सेंटर द्वारा डॉ. राजाराम त्रिपाठी के नेतृत्व में विकसित नेचुरल ग्रीनहाउस मॉडल किसानों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपूर्वा त्रिपाठी के प्रदर्शन की सराहते हुए उन्हें सम्मानित किया गया तथा ग्रीन समिट विशिष्ट-सम्मान प्रदान किया गया।

चैतन्य देवियों की झाँकी बनीं आकर्षण का केन्द्र

रायपुर । प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा नवरात्रि पर नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-20 स्थित सेवाकेन्द्र में सजायी गई चैतन्य देवियों की झाँकी का जिन्दल जिन्दल स्टील एण्ड पावर कम्पनी के प्रेसीडेन्ट प्रदीप टण्डन, एन.आर.डी.ए. के पूर्व चेयरमैन एस.एस. बजाज, जीएसटी के असिस्टेन्ट कमिश्नर शैलेन्द्र पाटले और ब्रम्हाकुमारी सविता दीदी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। झाँकी का अवलोकन करने के बाद जिन्दल जिन्दल स्टील एण्ड पावर कम्पनी के प्रेसीडेन्ट प्रदीप टण्डन ने कहा कि राजयोग साधनारत ब्रम्हाकुमारी बहनें जब अपलक देवियों के रूप में विराजित होती हैं तो यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि यह सजीव हैं या जड़ मूर्तियाँ हैं। इनके सम्मुख बैठने से मानसिक शान्ति के साथ साथ बेहद आत्मियता और अलौकिकता की अनुभूति होती है।

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 10 तक

रायपुर। जिला पंचायत कोण्डागांव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला एवं विकासखण्ड स्तर के सहायक अभियंता, लेखापाल, विकासखण्ड समन्वयक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु उक्त पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफा में केवल स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ.ग.) के पते पर निर्धारित तिथि 10 अक्टूबर 2024, समय सांय 5.30 बजे तक आमंत्रित किया गया है।

सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी युवाओं के लिए प्रेरणा का अद्वितीय स्रोत : राज्यपाल

रायपुर। रायपुर में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह युवाओं के लिए प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत है। यह दिखाता है कि भारतीय सेना में शामिल होने का अर्थ केवल एक नौकरी पाना ही नहीं है बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पण की भावना से ओत-प्रोत होना है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज रायपुर में सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन अवसर पर उक्त बातें कहीं।

रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विगत 05 अक्टूबर से आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज भव्य समारोह में समापन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि भारतीय सेना राष्ट्र सेवा का प्रतीक है, इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सैन्य प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं में साहस और समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। छत्तीसगढ़ के युवा भी सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे और देश की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। श्री डेका ने कहा कि यह आयोजन हमे दिखाता है कि भारतीय सेना अब अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों से सुसज्जित है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा बढ़ता हुए कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रगति की है। भीष्म टी-90 टैंक, स्ट्रेला मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण जो हम यहां देख रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि अपने संसाधनों और प्रतिभा का उपयोग करके हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकतों में से एक बन रहे है।उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य और वीरता अद्भुत है। हर सैनिक में त्याग, साहस और कर्तव्यपरायणता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। इसमे महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वे भी सेना के हर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। हमारे जवानों का अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा हमे यह सिखाता है कि जब देश की बात हो तो हमे सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि आपदा राहत कार्यों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और शांति बनाए रखने के प्रयासों और जीवन के साथ हमारी सम्पत्ति की रक्षा करती है। इसलिए हमारे सैनिकों और उनके परिजनों के हित और कल्याण के लिए हमें भी अधिक-अधिक योगदान करना चाहिए। समारोह के पूर्व श्री डेका ने सैन्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेना के उच्च अधिकारियों ने भीष्म टी-90 टैंक सहित विभिन्न मिसाइल, अत्याधुनिक लड़ाकू हथियारों एवं अन्य सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल श्री डेका ने शहीद जवानों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में स्वागत भाषण रायपुर जिले के कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह ने किया। समारोह के दौरान एनसीसी के कैडेटों का शानदार घुड़सवारी प्रदर्शन, जाबांज सैनिकों का डेयर डेविल मोटर साइकिल शो, गोरखा रेजिमेंट का खुखरी डांस प्रस्तुतिकरण, हेलीकॉप्टर से सलामी, सैन्य छापेमारी, मिलिट्री बैंड कॉन्सर्ट एवं अन्य विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ और ओड़िशा उप क्षेत्र के ब्रिगेडियर अमन आंनद को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मानपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। सेना के अधिकारियों ने उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, श्री रामप्रताप सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक श्री विवेक शर्मा, सेना के अधिकारीगण, सैनिक, उनके परिजन, आम जनता, युवा,महिलाएं तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

जन जागरूकता पखवाड़ा: पुलिस चौक-चौराहों पर दे रही साइबर क्राइम से बचने की जानकारी

रायपुर। रायपुर पुलिस ने 5 अक्टूबर को साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत विभिन्न रास गरबा आयोजन स्थलों, दुर्गा पंडालों, मेलों और चौक-चौराहों पर नागरिकों को साइबर अपराध से बचने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

रायपुर पुलिस की साइबर टीमें विभिन्न स्थानों पर जाकर आम जनता, खासकर छात्रों और राहगीरों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही हैं। जागरूकता के लिए पाम्पलेट बांटे गए और प्रमुख चौक-चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अब तक 2700 से अधिक छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूक किया गया। वहीं देवेन्द्र नगर चौक, आमानाका चौक, जयस्तंभ चौक और गौरव पथ में डिजिटल स्क्रीन पर साइबर अपराध से संबंधित वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस की साइबर और थानों की टीमें विभिन्न चौक-चौराहों और कार्यालयों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। इनमें प्रमुख स्थानों पर रास गरबा स्थल, मॉल, और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान शामिल हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए जानकारी साझा की जा रही है और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ टीमों द्वारा नागरिकों के सवालों का उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। रायपुर पुलिस द्वारा रात के समय भी मॉल्स, आयोजन स्थलों और अन्य स्थानों पर साइबर अपराध से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह अभियान 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से नागरिकों को सुरक्षित और जागरूक बनाना है।

रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा

रायपुर। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में गुरुवार को बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद दल ने निगम द्वारा अवैध रूप से बनाई गईं तीन दुकानों को लेकर सत्ता पक्ष पर तीखे सवाल दागे। आरोप है कि निगम ने भू-अभिलेख शाखा की जमीन पर बिना अनुमति के दुकानें खड़ी कर दी हैं। दुकानों को व्यवस्थापन के नाम पर बनाया गया, लेकिन शासन से इसकी मंजूरी तक नहीं ली गई।

इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों ने भी अपनी ही पार्टी के मेयर इन काउंसिल को घेरा, जिससे सत्ताधारी पक्ष पर दबाव बढ़ गया। आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तीन दुकानें अवैध रूप से बनाई गईं, जिससे पार्षदों के बीच गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अधिकारियों के निलंबन की मांग की, जिसके बाद आयुक्त और सभापति ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सामान्य सभा में एजेंडा क्रमांक 23, जिसमें कांजी हाउस की दुकान के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव था, सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया।

पार्षदों ने आरोप लगाया कि इस एजेंडे को षड्यंत्रपूर्वक सभा में लाया गया था और इसमें निगम अधिकारियों की मिलीभगत है। बैठक में टिकरापारा के नरैया तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसे पहले ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही खम्हारडीह में नई पानी टंकी के निर्माण और शहर में स्वीपिंग मशीन से सफाई का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत की जा रही है। निगम की इस बैठक में अवैध निर्माण और व्यवस्थापन के मुद्दों पर अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिससे नगर निगम की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है।

नन्हें फरिश्ते अभियान : अब तक 507 बच्चों की सकुशल घर वापसी

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) न सिर्फ रेल यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा में जुटा है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। आरपीएफ द्वारा जरूरतमंद यात्रियों की मदद के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते के तहत जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक 507 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का सफल अभियान चलाया है। इस अभियान में 298 बालक और 209 बालिकाओं को विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों से रेस्क्यू कर, उन्हें गैर-सरकारी संगठनों व उनके अभिभावकों को सौंपा गया। रेलवे सुरक्षा बल का यह प्रयास न केवल उनकी सतर्कता का परिचय देता है, बल्कि उनके सामाजिक कर्तव्यों के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। साथ ही, आरपीएफ द्वारा चौबीस घंटे हेल्पलाइन सेवा और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों को त्वरित सहायता दी जाती है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में महिला आरपीएफ स्टाफ की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा, रात्रि में चलने वाली संवेदनशील ट्रेनों की सुरक्षा के लिए विशेष एस्कॉर्ट टीमों और डिकॉय टास्क फोर्स की तैनाती की गई है, जो चोरी, नशाखोरी और अन्य अपराधों पर कड़ी नजर रख रही हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का आरपीएफ स्टाफ पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, और उनके इन प्रयासों की जनता द्वारा सराहना की जा रही है।

माता कर्मा हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैः साहू

साहू समाज बोरियाखुर्द का शपथ ग्रहण समारोह

रायपुर. कर्मा झेरिया साहू समाज वार्ड नंबर 54 बोरियां खुर्द रायपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष अंगेश कुमार साहू, उपाध्यक्ष भुनेश्वर साहू, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती मंजूलता छोटेलाल साहू एवम् मनोनित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मोती लाल साहू ने कहा कि माता कर्मा हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। विधायक श्री साहू ने सभी नव निर्वाचित एवम् मनोनित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए साहू समाज की एकजुटता बनाएं रखने एवम् आपसी मतभेद को भूलकर एक साथ चलने की सलाह दिए ,फिर साहू समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे टिकरापारा परिक्षेत्र के अध्यक्ष श्री गिरधर साहू ने कहा कि आपसी मनमुटाव को भुलाकर निरंतर सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए समाज को जोड़ने की बात कहीं। विधायक साहू ने साहू समाज के जीर्णोधार के लिए विधायक निधि से स्वीकृत राशि तीन लाख रुपए का भूमिपुजन किया साथ समाज के लिए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि श्री चंद्रहास निर्मलकर ने शौचालय निर्माण के लिए एक लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पी के साहू समाज सेवी श्री मनहरण साहू, शहर जिला साहू संघ के उपाध्यक्ष सोमनाथ साहू, परिक्षेत्र उपाध्यक्ष डा यशवंत साहू, वार्ड अध्यक्ष क्रमश बेनी राम साहू, खुबी राम साहू, टीका राम साहू सहित प्रदेश, जिला परिक्षेत्र एवम् वार्ड के स्वजाति बंधु बढ़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम में एकता डांस ग्रुप द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम अरपा पैरी के धार, जय हो जय छत्तीसगढ़ मईया गीत पर शानदार प्रस्तुति दी कार्यक्रम का मंच संचालन नारायण साहू के द्वारा किया गया अंत में आभार प्रदर्शन छोटेलाल साहू ने किया।

मनेन्द्रगढ़ में खुलेगा बेवरेज डिपो

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक सोमवार को रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कारपोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कार्पोरेशन द्वारा दुर्ग एवं बिलासपुर के गोदामों में हाउस कीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने कार्य का अनुमोदन किया गया, साथ ही अरसनारा-दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जेनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष जायसवाल ने सरगुजा संभाग में वाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आस पास के जिलों में स्टाक उपलब्धता के लिए मनेंद्रगढ़ में बेवरेज डिपो या गोदाम के संचालन का प्रस्ताव रखा जिस पर संचालक मंडल ने अपनी सहमति प्रदान की।]

मनेन्द्रगढ़ में बेवरेज गोदाम खुलने से गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिलों को वाइन दुकानों के लिए स्टाक का स्टोरेज किया जाएगा।

जनजातियों में आत्मसम्मान से जीने कला दूसरे समाज को सीखा चाहिए : टेकाम

रायपुर। जनजातियों के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और जनजातीय महानायकों के बलिदान को आमजनों को बताने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्तमान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने जनजातियों के ज्ञान और परंपराओं को दूसरे समाजों के लिए भी अनुकरणीय बताया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में सहभागिता, प्रकृति प्रेम के साथ आत्म स्वाभिमान से जीने की कला को दूसरे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। टेकाम ने इस दौरान जनजातीय समाज को भारत के संविधान को मिली सहूलियतों और संरक्षण के साथ विकास के लिए किए गए प्रावधानों को भी लोगों को बताया।

इस दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती भी मनाई गई और रानी दुर्गावती के अपने गोंडवाना प्रदेश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने के वृत्तांत पर भी प्रकाश डाला गया है। कार्यशाला में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दो सौ से अधिक छात्र-छात्राओं एवं नागरिक शामिल हुए। कार्यशाला में जनजातीय समाज के महानायकों के बलिदान को भी इंगित किया गया। वक्ता वैभव सुरंगे ने भारत में जनजातीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम में

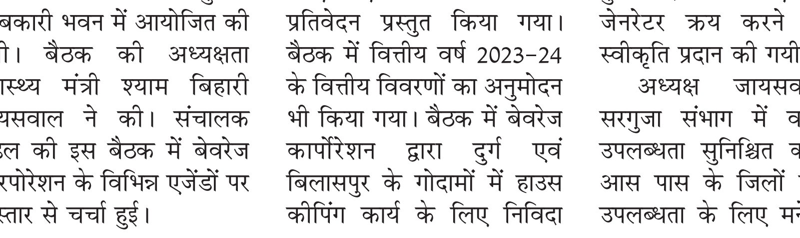

उनके योगदान पर विस्तृत जानकारी दी। भारत के प्रथम शहीद तिलका मांझी, वीर नारायण सिंह,गेंदसिंह, गुण्डाधुर आदि से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय समाजों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरूद्ध हुए संघर्ष को विस्तार से बताया है।

कार्यशाला में पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने जनजातीय समाज की परंपराओं, उनके रीतिरिवाजों और संस्कृति पर अपने नजरिए से रिसर्च किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने जनजातीय समाज पर होने वाले शोधों से आधुनिक विकास के क्रम का ज्ञान होने की भी बात कही।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय अस्मिता और गौरवशाली अतीत को वैश्विक पहचान देने के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसामुंडा की 150वीं जयंती पर सभी जिलों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है।

इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय के संबद्ध सभी महाविद्यालयों में जनजातीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, अस्मिता और जनजातीय महानायकों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला में वनवासी विकास समिति के प्रांत अध्यक्ष उमेश कच्छप, कुलसचिव डॉ शैलेन्द्र कुमार पटेल, और समन्वयक डॉ बंसो नुरूटी भी मौजूद रहे।

जयशंकर के पाकिस्तान दौरे के मायने

डॉ धनंजय त्रिपाठी

घाई सहयोग संगठन की दो दिवसीय वार्षिक बैठक 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हो रही है. इस आयोजन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे. लगभग एक दशक के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री या अधिकारी की पाकिस्तान यात्रा होगी. ऐसे में स्वाभाविक है कि इस दौरे को लेकर उत्सुकता बहुत है और इस कारण इसके बारे में चर्चा भी खूब हो रही है. साल में इस संगठन की दो बैठकें होती हैं. एक में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं और दूसरे में शासनाध्यक्ष. इनके प्रतिनिधि के तौर पर वरिष्ठ मंत्री भी आयोजनों में भाग लेते हैं. भारत में 2023 में ये बैठकें हुई थीं, जिनमें से एक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आये थे. प्रमुखों की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई थी. बीते सालों में, खासकर 2019 से, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत गिरावट आयी है. हालांकि जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि उनकी यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए है, न कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए.

इस यात्रा को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं. पाकिस्तान के रवैये और द्विपक्षीय मसलों के कारण भारत सार्क सम्मेलन में हिस्सेदारी को लेकर हिचकता रहा है, जो पाकिस्तान में होना प्रस्तावित है. इस कारण वह बैठक नहीं हो पा रही है. ऐसे में विदेश मंत्री का जाना महत्वपूर्ण हो जाता है. दूसरी बात यह है कि क्या इससे हम द्विपक्षीय संबंधों के मामले में कुछ अपेक्षा कर सकते हैं. क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों की कोई बातचीत होगी और क्या इससे भविष्य में वार्ता के लिए कोई रास्ता खुल सकता है? पाकिस्तान में एक नयी सरकार सत्ता में है और उसकी ओर से भी ऐसे संकेत दिये गये हैं कि वह भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं हो पा रही थी, इसके लिए कोई सिरा नहीं मिल पा रहा था, शायद उसके लिए एक अवसर मिल सकेगा. जयशंकर ने ऐसा कोई संकेत तो नहीं दिया है, पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह जरूर कहा है कि वह वापस आकर बतायेंगे कि वे दोनों देशों के संबंधों को कैसे परिभाषित करते हैं. तो, हमें उम्मीद के साथ कुछ इंतजार करना चाहिए.

शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक का महत्व इस वजह से बहुत बढ़ जाता है कि अभी दुनिया में अनेक गंभीर भू-राजनीतिक संकट हैं और स्थितियां किस दिशा में जायेंगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है. इस संगठन में रूस और चीन जैसी शक्तियों के साथ भारत, पाकिस्तान और ईरान भी सदस्य हैं तथा मध्य एशियाई गणराज्य भी इसके हिस्से हैं. अभी ईरान और इस्राइल के बीच के संघर्ष को लेकर दुनिया चिंतित है. इस बैठक में इस पर अवश्य चर्चा होगी. रूस-यूक्रेन युद्ध तो एक गंभीर मसला है ही. तुर्की और बांग्लादेश जैसे देश इस संगठन के संवाद सहभागी हैं और अनेक देश इस समूह की सदस्यता भी लेना चाहते हैं. तो, पश्चिम एशिया को लेकर बातचीत अपेक्षित है. अफगानिस्तान भी समूह का सदस्य है, पर तालिबान को मान्यता न होने के कारण उसकी सदस्यता अभी निष्क्रिय है. कुछ दिन पहले रूस में दस देशों के एक समूह की अफगानिस्तान को लेकर बैठक हुई है, जिसमें तालिबान शासन के प्रतिनिधि भी थे. उक्त समूह में भारत भी शामिल है. विशेष रूप से चीन और रूस की ओर से ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि तालिबान के साथ आधिकारिक संपर्क बने और उसे मान्यता दी जाए या उस जैसी कोई व्यवस्था हो. इस पर भी बातचीत अपेक्षित है.

पश्चिम एशिया का संकट हो या रूस-यूक्रेन युद्ध, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों पर इन घटनाओं का असर पड़ रहा है. इसी माह रूस में ब्रिक्स समूह का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. संगठन के अनेक सदस्य ब्रिक्स के सदस्य या पर्यवेक्षक हैं. इस आलोक में भी इस्लामाबाद की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है. यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है. इसका मुख्य सरोकार सुरक्षा को लेकर है.

मुस्लिम आइडेंटिटी से पहले 'देश' होता है

आमना बेगम

इज़रायल द्वारा हसन नसरल्लाह की हत्या ने हिजबुल्लाह को करारा झटका दिया है. भू-राजनीतिक दृष्टि से, हिजबुल्लाह नेता की हत्या को बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बदला नहीं जा सकता. यह घटनाक्रम या तो हिजबुल्ला के मनोबल को खत्म कर सकता है या उसके सदस्यों के गुस्से को भड़का सकता है और उन्हें उकसा सकता है. लेकिन आम तौर पर, जब एक नेता जिसकी पहचान का आधार धर्म है, उसे खत्म कर दिया जाता है, तो ऐसे संगठनों की प्रभावशीलता कम हो जाती है. एक नए नेता के लिए तुरंत उसी स्तर की पकड़ बना पाना और प्रभाव हासिल कर पाना मुश्किल होता है.

राजनीतिक और उग्रवादी शाखाओं में विभाजित हिजबुल्लाह को अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन, यूरोपीय संघ और अरब लीग सहित कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. हालांकि मध्य पूर्वी भू-राजनीति में इस समूह की भूमिका के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा, वह है नसरल्लाह की मौत पर दुनिया भर में हुई प्रतिक्रिया, विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों के बीच.

इनमें से कुछ बहुत ही परेशान करने वाले हैं- जैसे कि सोमवार शाम को दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित प्रार्थना और शोक सभा, जिसमें नसरल्लाह और अन्य हिजबुल्लाह अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई.

नसरल्लाह की मौत के जवाब में मुख्य रूप से शिया संगठनों द्वारा आयोजित कई विरोध रैलियां भी हुईं.

दिशाहीन एकजुटता

यह देखना निराशाजनक है कि मुसलमानों का एक वर्ग और विशेष रूप से उनका नेतृत्व इस तरह के घटनाक्रमों के इर्द-गिर्द की बारीकियों और जटिलताओं को स्वीकार करने में विफल रहता है, खासकर भारत के अपने आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए. उनके बयान और कार्य हिजबुल्लाह और उसके इजरायल-विरोधी रुख के साथ धार्मिक एकजुटता से प्रेरित हैं, जबकि वे खुद को चरमपंथी उग्रवाद से अलग करने की आवश्यकता की अनदेखी करते हैं. जब प्रमुख मुसलमान चेहरे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी

करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में मुस्लिम होने की भावना के इर्द-गिर्द मुसलमानों को एकजुट करते हैं, तो वे मुस्लिम समुदाय और राष्ट्र दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं.

कई आम मुसलमान, खास तौर पर पसमांदा मुसलमान, मध्य पूर्वी भू-राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वे आसानी से अपने साथी मुसलमानों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए हिजबुल्लाह के साथ सहानुभूति रख सकते हैं. हालांकि, असली मुद्दा उन प्रमुख लोगों के साथ है जो जटिलताओं को समझते हैं और फिर भी भावनात्मक राजनीति करना चुनते हैं. ये नेता, जिन्हें राष्ट्रीय हितों और भारतीय मुसलमानों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, या तो कबीलाई वफ़ादारी में फंसे हुए हैं या सत्ता हथियाने की ख़तरनाक इच्छा दिखाते हैं, चाहे इससे समुदाय और राष्ट्र के हितों का कितना ही नुकसान क्यों न हो.

मानवाधिकारों का दोहरा मापदंड

हिजबुल्लाह को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित करने में भारत की स्पष्ट अनिच्छा को अक्सर उसके प्रति सहानुभूति के बहाने के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. फिर भी, दो-राज्य समाधान के पक्ष में भारत के आधिकारिक रुख के बावजूद, इज़रायल की निंदा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है. तर्क अक्सर मानवाधिकारों की ओर मुड़ जाता है, जो अपने आप में समस्या वाली बात नहीं है- अपने सह-धर्मियों के अधिकारों के लिए खड़ा होना समझ में आता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि मानवाधिकारों के प्रति यह चिंता अन्य संदर्भों में क्यों नहीं जताई जाती?

हमारे पड़ोसी देशों में मानवाधिकारों के हनन की बात आने पर इतनी आवाज़ क्यों नहीं उठती? ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि भारत में ही मानवाधिकारों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता. उदाहरण के लिए, कश्मीरी अल्पसंख्यकों के अधिकार या उससे भी ज़्यादा व्यापक रूप से मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के अधिकारों को नज़रअंदाज़ किया जाता है या दरकिनार कर दिया जाता है. मानवाधिकारों के लिए यह चुनिंदा चिंता बताती है कि यह मुद्दा सिद्धांतों से ज़्यादा राजनीति और भावुकता से जुड़ा है- जो सिर्फ़ यही साबित करता है कि उनके तर्क में कोई विश्वसनीयता नहीं है.

क्या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से अशराफ़ अभिजात वर्ग करता है, ने कभी हिंदुओं, ईसाइयों या यहां तक कि सिखों के मानवाधिकारों को स्वीकार करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया है? मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता.

फिर भी, उन्होंने हिजबुल्लाह जैसे संगठन के एक नेता को सम्मानित करना उचित समझा, जिसे कि कई अरब देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है.

जबकि आईआईसीसी का उद्देश्य इस देश के लोगों के बीच आपसी समझ और सौहार्द्र को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके कार्य इसके विपरीत संकेत देते हैं.

इससे आईआईसीसी की प्राथमिकताओं और समावेशिता तथा आपसी समझ को बढ़ावा देने की इसकी वास्तविक प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठते हैं. ऐसा लगता है कि यह भारत में मुसलमानों सहित सभी समुदायों को प्रभावित करने वाले ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने के बजाय अशराफ अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करने से अधिक प्रेरित है.

मैं कहूंगी कि पसमांदा मुस्लिम नेताओं ने आईआईसीसी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाकर सही काम किया है, यहां तक कि उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करने में इसकी सीमित भूमिका को देखते हुए सरकार को इसे अस्पताल में बदल देना चाहिए.

लेकिन पसमांदाओं के बीच भी हिजबुल्लाह के प्रति प्रतिक्रिया कम रही है.

प्राथमिकताओं का संकट

अतीत में, समुदाय के एक प्रमुख संगठन पसमांदा मुस्लिम महाज ने इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार के रुख के साथ तालमेल बिठाया था, और हमास द्वारा नागरिकों पर हमले की निंदा की थी. लेकिन संगठन ने हिजबुल्लाह पर कोई बयान जारी नहीं किया, जो भारतीय मुसलमानों के बीच एक सामूहिक वास्तविकता को दर्शाता है. समुदाय या तो नसरल्लाह की मौत पर शोक मना रहा है या उदासीन बना हुआ है. दोनों ही बातें खराब हैं. भारत में अन्य समुदायों के एक वर्ग को भारतीय मुसलमानों का यह कृत्य इस हद तक कबीलाई लगता है कि वे आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं.

दुखद वास्तविकता यह है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय में ऐसी धारणाओं या सामान्यीकरणों का मुकाबला करने के लिए सामाजिक पूंजी का अभाव है. और यह कैसे हो सकता है, जब इसके अभिजात वर्ग चरमपंथी तत्वों का महिमामंडन करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं? समुदाय के नेता समुदाय के कल्याण की तुलना में भावना, धर्म और पीड़ित होने के राजनीतिकरण पर ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं. समुदाय के रोल मॉडल वे लोग नहीं हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, मानवता की सेवा की है या राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, बल्कि वे लोग हैं जो निरंतर टकराव में फंसे रहते हैं.

समुदाय के भीतर सामान्य राजनीतिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है ताकि स्वीकार्य विचारों और चर्चाओं की सीमा संकीर्ण और पुरातन मानसिकता और नैरेटिव से परे हो.

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

उपनिषद्-ग्रंथ

गतांक से आगे...

(100) तान् उपदिशति पुराणं वेदः । (शतपथ 13 ।4 ।3 ।13) अर्थात् - [यज्ञाधिष्ठाता] उन्हें उपदेश करे कि पुराण वेद हैं।

(101) ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथाः नाराशंसीरिति । (तैत्तिरीयारण्यक 2 । 6) अर्थात् ब्राह्मण इतिहास पुराण आदि (सब वेद के ही समान हैं) (102) अथ नवमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत ।

(शतपथ 13 ।4 ।3 । 12 । 13) अर्थात् - यज्ञ में नौवें दिन कुछ पुराण का पाठ किया जाय । वेद के ब्राह्मणभाग में किस प्रकार ग्रन्थवाची पुराण शब्द का बार-बार उल्लेख मिलता है- यह उपर्युक्त प्रमाणों द्वारा भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। कई पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि नरपुङ्गव दुराग्रड्वश उपयुक्त प्रमाणो का अपलाप करने के लिये यह कह उठा करते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में पुराण शब्द का अर्थ पुराण-विद्या% है जो कि वेद के ही विशिष्ट मन्त्रों में वर्णित है। हमारे विचार में यह उत्तर भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः का सर्वाङ्गसुन्दर उदाहरण है; क्योंकि पुराण शब्दः के सम्बन्ध में यदि यह नियम ठीक है तो इतिहास शब्द का अर्थ भी इतिहास-विद्या होगा और उसका अस्तित्व भी वेद-मन्त्रों में ही स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसी दशा में वेदों को अनैतिहासिक सिद्ध करने वाले यही लोग अनिष्टापत्ति की उभयपाशा रज्जु में निबद्ध हो जायेंगे । वास्तव में जिस इतिहास-सम्बद्ध पुराण का उक्त प्रमाणों में वर्णन है वह वर्तमान अष्टादश पुराणों की मूलभूत सामग्री का सर्वस्व एक ही ग्रन्थ था जो गुरुपरम्परा से प्रचारित था। कहना न होगा कि उसी का विकसित रूप वर्तमान पुराण हैं।

वेद-मन्त्रभाग- (103) तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । (ऋग् 616614) अर्थात् - [सायणभाष्यानुसारी भाषार्थ (पुनानं-पूयमानं)

क्रमशः ...

वर्ल्ड कॉटन डे

वर्ल्ड कॉटन डे, जिसे हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, कपास की फसल के महत्व को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, इस दिन का उद्देश्य कपास की खेती और उससे जुड़े समुदायों की समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाना है, 2019 में इसे सारे राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली, जिससे इसकी वैश्विक महत्ता को स्वीकार किया गया, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, किसान और उद्योगपति एक मंच पर आते हैं, यह दिन कपास के योगदान को पहचानने और उसे समर्थन देने का प्रेरणादायक अवसर है, यहां है इस दिन से जुड़े सवालों के जबाब-

1. वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है?- वर्ल्ड कॉटन डे हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे पहली बार 2019 में सारे राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी, इस दिन का उद्देश्य कपास के उत्पादन और इसके वैश्विक महत्व को उजागर करना है, यह दिन कपास से जुड़े सभी हितधारकों को एक साथ लाने का भी एक अवसर है, विभिन्न देशों में इस दिन को अलग-अलग तरीके से मनाने की परंपरा है.

2. इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है?-इस दिन का मुख्य उद्देश्य कपास की खेती और उद्योग के महत्व को बढ़ावा देना है, यह किसानों, श्रमिकों और संबंधित समुदायों की समस्याओं को उजागर करता है, इसके अलावा, यह कपास के सतत उत्पादन और उसके पर्यावरणीय प्रभाव पर भी चर्चा करने का अवसर देता है। जागरूकता फैलाने के माध्यम से, यह फसल की आर्थिक स्थिरता को भी समर्थन करता है, यह कृषि और फैशन उद्योग में कपास की भूमिका को समझने में मदद करता है.

3. कपास का क्या महत्व है?- कपास एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है, जो दुनियाभर में कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह न केवल कपड़े बनाने के लिए उपयोग होता है, बल्कि इसके कई औद्योगिक उपयोग भी हैं, कपास की खेती लाखों किसानों के लिए आजीविका का साधन है। इसके अलावा, कपास की फसल से जुड़े उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर है, यह वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है.

4. किस तरह के कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं?- वर्ल्ड कॉटन डे के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे सेमिनार और कार्यशालाएं, इनमें कपास की खेती, उसके लाभ और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, इसके अलावा, प्रदर्शनी भी लगाई जाती हैं, जहां कपास के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है, कई देशों में कृषि प्रदर्शनी और फसल दिवस भी मनाए जाते हैं, इस दिन विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं.

5. क्या वर्ल्ड कॉटन डे का कोई ऐतिहासिक महत्व है?-हां, वर्ल्ड कॉटन डे का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी, इससे कपास की वैश्विक महत्ता को ऑफिशियल परमिशन मिली, इस दिन के माध्यम से, विश्व कपास उद्योग और इसके जुड़े समुदायों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यह दिन कपास की फसल के विकास और उसके पर्यावरणीय प्रभाव पर भी विचार करने का अवसर प्रदान करता है, यह कृषि और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है.

6. किस तरह से लोग इस दिन को मनाने में भाग ले सकते हैं?- लोग इस दिन को मनाने में कई तरीकों से भाग ले सकते हैं, जैसे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर। सोशल मीडिया पर इस विषय में जानकारी साझा करके जागरूकता फैलाना भी एक तरीका है, कपास से जुड़े उत्पादों को खरीदकर और उनके महत्व को समझकर भी लोग योगदान कर सकते हैं, इसके अलावा, लोग किसानों और श्रमिकों के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं, इस दिन को मनाने का एक और तरीका कपास की खेती से जुड़े आयोजनों में भाग लेना

इस्राइल के साथ हिजबुल्ला-हमास की लड़ाई और रूस-यूक्रेन युद्ध के पीछे के वैश्विक पैटर्न को समझें

थॉमस एल फीडमैन

इस्राइल द्वारा हिजबुल्ला पर किया गया विनाशकारी हमला क्यों और कैसे ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और यहां तक कि चीन के लिए भी दुनिया को हिला देने वाला खतरा बन गया है, यह समझने के लिए हमें इसको उस व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा, जिसने आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शीतयुद्ध का स्थान ले लिया है। पिछले वर्ष सात अक्तूबर को इस्राइल पर हमास के हमले के बाद मैंने कहा था कि अब हम शीतयुद्ध या शीतयुद्ध के बाद के दौर में नहीं हैं। हम 'शीतयुद्ध के बाद के दौर के बाद के युग' में हैं। इसमें सभ्य देशों के अस्थायी समावेशी गठबंधन और रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गठबंधन के बीच संघर्ष चल रहा है।

समावेशी गठबंधन में शामिल सभी देश लोकतांत्रिक नहीं हैं, पर अपने भविष्य को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सुरक्षित मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को आर्थिक एकीकरण, खुलेपन और सहयोग के लिए प्रेरित कर रहा है। जबकि प्रतिरोधी गठबंधन में शामिल देशों का शासन क्रूर और अधिनायकवादी है, जो समावेशी दुनिया के प्रति अपने विरोध का उपयोग अपने समाजों के सैन्यीकरण को उचित ठहराने और सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए करता है। चीन दोनों खेमों में बंटा हुआ है, क्योंकि समावेशी गठबंधन तक पहुंच पर ही उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है,

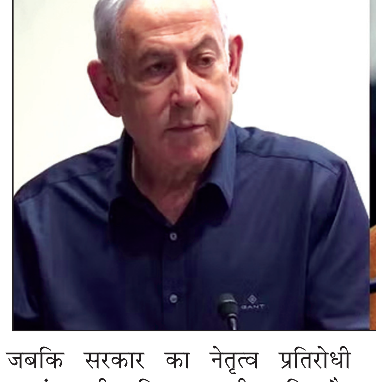

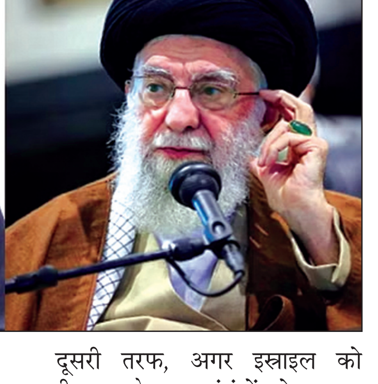

जबकि सरकार का नेतृत्व प्रतिरोधी गठबंधन की अधिनायकवादी प्रवृत्ति और हितों को साझा करता है।

यूक्रेन, गाजा और लेबनान में चल रहे युद्धों को इस वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा। यूक्रेन यूरोप की समावेशी दुनिया में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। वह रूस के दायरे से आजाद होकर यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता था। इस्राइल और सऊदी अरब संबंधों को सामान्य बनाकर पश्चिमी एशिया में समावेशी दुनिया का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। रूस ने यूक्रेन को पश्चिम (यूरोपीय संघ और नाटो) में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया और ईरान, हमास और हिजबुल्ला ने इस्राइल को पूर्व (सऊदी अरब के साथ संबंध) में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो जाता है, तो यूरोप के %संपूर्ण और स्वतंत्र% होने की समावेशी दृष्टि लगभग पूरी हो जाएगी और रूस में व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाएंगे।

दूसरी तरफ, अगर इस्राइल को सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की अनुमति दी गई, तो इससे न केवल उस क्षेत्र में समावेशी गठबंधन का व्यापक विस्तार होगा, बल्कि यह ईरान और लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक में ईरान समर्थक शिया लड़ाकों के दुस्साहसी प्रतिनिधियों को लगभग पूरी तरह से अलग-थलग कर देगा, जो सभी अपने मुल्कों को विफल राष्ट्र में तब्दील कर रहे हैं। वास्तव में, यह कहना कठिन है कि हिजबुल्ला और उसके नेता हसन नसरल्ला, जो इस्राइली हमले में मारे गए, से लेबनान और सुन्नी व ईसाई अरब जगत के कई हिस्सों में लोग कितनी नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने लेबनान का अपहरण कर उसे ईरानी साम्राज्यवाद का अड्डा बना दिया था।

पिछले दिनों मैं ओरिट पेर्लोव से बात कर रहा था, जो इस्राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के लिए अरब सोशल मीडिया पर नजर रखती हैं। उन्होंने बताया कि लेबनानी लोग नहीं चाहते कि बेरूत को गाजा की तरह नष्ट कर दिया जाए और वे वास्तव में गृहयुद्ध की वापसी से डरते हैं। लेकिन नसरल्ला के अंत को लेबनानी, इस्राइली और फलस्तीनी लोगों के लिए स्थायी रूप से बेहतर भविष्य में तब्दील करने के लिए अभी बहुत सारे कूटनीतिक कार्य किए जाने बाकी हैं। बाइडन-हैरिस प्रशासन अस्थायी समावेशी गठबंधन को रणनीतिक महत्व देने के लिए एक नेटवर्क बना रहा है। पूरी परियोजना का मुख्य बिंदु इस्राइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का बाइडन टीम का प्रस्ताव है, जिसके लिए सऊदी अरब तैयार है, बशर्ते इस्राइल पश्चिमी तट में फलस्तीनी प्राधिकरण के साथ द्वि-राष्ट्र समाधान पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो। और समस्या यहीं पर आती है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण पर बारीकी से ध्यान दें, तो वह प्रतिरोधी और समावेशी गठबंधनों के बीच संघर्ष को अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में, यह उनके संयुक्त राष्ट्र भाषण का केंद्र बिंदु था।

उन्होंने अपने संबोधन के दौरान दो नक्शे दिखाए, एक का शीर्षक था 'आशीर्वाद' और दूसरा 'अभिशाप'। अगर आप 'अभिशाप' वाले नक्शे को ध्यान से देखें, तो इसमें इस्राइल तो दिखाया गया है, लेकिन गाजा और इस्राइली कब्जे वाले पश्चिमी तट के साथ कोई सीमा नहीं दिखाई गई है (जैसे कि इसे पहले ही जोड़ दिया गया हो, जो इस्राइल का लक्ष्य भी है)। और यही समस्या है। नेतन्याहू दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि ईरान और उसके समर्थक यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक फैले समावेशी दुनिया की मुख्य बाधा हैं। मैं इससे असहमत हूं। इस पूरे गठबंधन का आधार सऊदी-इस्राइल सामान्यीकरण है, जो इस्राइल और उदारवादी फलस्तीनियों के बीच सुलह पर आधारित है।

यदि इस्राइल अब आगे बढ़ता है और एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण, जिसने ओस्लो शांति संधि को पहले ही स्वीकार कर लिया है, के साथ दो राष्ट्रों पर बातचीत शुरू करता है, तो यह कूटनीतिक झटका होगा, जो इस्राइल द्वारा हिजबुल्ला और हमास को दिए गए सैन्य झटके को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में 'प्रतिरोधी' ताकतें पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाएंगी और उनकी झूठी ढाल छीन ली जाएगी कि वे फलस्तीनी मुद्दे के रक्षक हैं। ईरान, हमास, हिजबुल्ला एवं रूस और यहां तक कि चीन के लिए भी इससे बड़ा कोई झटका नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए नेतन्याहू को हिजबुल्ला, जिसे पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, के नेतृत्व को खत्म करने के सैन्य जोखिम से भी बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना होगा। 'समावेशी दुनिया' और 'प्रतिरोधी दुनिया' के बीच संघर्ष कई बातों पर आधारित है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेतन्याहू लेबनान में 'पार्टी ऑफ गॉड' पर किए गए प्रहार के बाद इस्राइल में उनको समर्थन दे रही 'पार्टी ऑफ गॉड' के जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक संपूर्ण भू-भाग पर इस्राइली नियंत्रण के इरादों पर भी वैसा ही राजनीतिक प्रहार करें।

आज का इतिहास

2004 में आज ही के दिन केन्या के पर्यावरणविद वांगरी मथाई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

2004 में 8 अक्टूबर के दिन ही भारतीय गेहूं पर मौनसेंटो का पेटेन्ट रद हुआ था।

2003 में आज ही के दिन ईरान की शिरीन इबादी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।

2003 में 8 अक्टूबर के दिन ही टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस वेनेजुएला गोजेदोर एजुआ ने खिताब जीता था।

2002 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का दोबारा टेस्ट किया था।

2000 में 8 अक्टूबर के दिन ही वोजोस्लाव कोस्तुनिका यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति बने थे।

1998 में आज ही के दिन भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था।

1996 में 8 अक्टूबर के दिन ही कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए थे।

1970 में आज ही के दिन सोवियत संघ के लेखक एलैकजेंडर सोल्जनित्सन को नोबेल पुरस्कार मिला था।

1932 में 8 अक्टूबर के दिन ही भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था।

1926 में 8 अक्टूबर के दिन ही बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार का जन्म हुआ था।

1844 में आज ही के दिन प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म हुआ था।

1936 में आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था।

1979 में 8 अक्टूबर के दिन ही संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था।

1990 में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी का निधन हुआ था।

बिहार में अपने लिए कितनी जगह बना सकेंगे प्रशांत किशोर

मनीष कुमार

दो साल पहले दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा से पदयात्रा की शुरुआत करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अभियान जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता व अगले दस वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने के संकल्प के साथ अंततः एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया.

सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के सहारे बदलाव की आकांक्षा रखने वाले प्रशांत किशोर (पीके) 17 जिलों के 5,500 गांवों की अपनी पांच हजार किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान राजनीति को जिम्मेदार बनाने का संदेश लोगों को देते रहे. इस दौरान उन्होंने आम जनों को यह समझाने की कोशिश की कि राजनीतिक दलों की रीति-नीति ही राज्य की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है.

अब अपने खुद के जन सुराज को एक राजनीतिक दल घोषित करने के मौके पर उन्होंने जय बिहार से अपनी बात की शुरुआत करते हुए बिहारियत का स्वाभिमान जगाने की कोशिश की और व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया. कार्यक्रम में जुटी भीड़ को दिए संबोधन में उन्होंने लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में लिया. बिहार की दुखती रग, खासकर शिक्षा और रोजगार की चर्चा करते हुए अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया.

पीएम मोदी की चाय पर चर्चा से लेकर बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है का नारा देने वाले प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं. हैदराबाद के संस्थान से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे यूनिसेफ से जुड़ गए. दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया, फिर 2010 में भारत लौटे. वाइब्रेंट गुजरात और चाय पर चर्चा जैसे कैंपेन से उनकी देशभर में पहचान बन गई.

2015 में वह नीतीश कुमार से जुड़े और फिर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के महागठबंधन को जीत दिलाकर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने. लेकिन, एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर विवाद के बाद पार्टी से अलग हो गए. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी और स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी के लिए भी पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति को अंजाम दिया. आखिरकार, उन्होंने बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की सोच के साथ उसी ऐतिहासिक गांधी आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत की, जहां से 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था.

राजनीतिक रणनीतिकार होने के नाते सभी पार्टियों की कमजोरी समझने वाले पीके का सब कुछ सुनियोजित था. अपनी पदयात्रा के दौरान भी वे उन मुद्दों को ही उठाते रहे. उनकी परिकल्पना ऐसा बिहार बनाने की है, जहां दूसरे राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में आएं. उन्होंने पूंजी, पढ़ाई और जमीन के जरिए गरीबी उन्मूलन का प्लान बताया.

पीके ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर बच्चों और किशोरों को रखा है. इनके लिए ऐसी विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिससे बड़े होकर वे बोझ न बन सकें. इस शिक्षा व्यवस्था के लिए अगले दस सालों में पांच लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जिसे वे शराबबंदी समाप्त कर उससे आने वाले राजस्व से जुटाएंगे. इसके बाद 15 से 50 वर्ष के लोगों के लिए उनकी पार्टी राज्य में ही 10-12 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था करेगी और इसके लिए आवश्यक धन वे साख-जमा अनुपात (क्रेडिट रेशियो) को संतुलित कर जुटाएंगे.

इसी तरह 60 साल से ऊपर के लोगों को प्रति माह दो हजार रुपये दिए जाएंगे. महिलाओं को रोजगार के लिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण देने की बात कही. अभी जीविका द्वारा दो-ढाई प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर उनकी सहायता की जा रही है. पीके ने किसानों के लिए खाने वाली नहीं, कमाने वाली खेती की बात कही. साथ ही यह भी बताया कि सत्ता में आने पर दस साल में बिहार को विकसित करने की कल्पना को साकार करने के लिए वे धन की व्यवस्था कैसे करेंगे.

राजनीतिक समीक्षक अरुण कुमार चौधरी कहते हैं, पहले भी प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में लोगों को उनके बच्चों के भविष्य का वास्ता देते रहे. वे कहते रहे हैं कि भले ही आधा प्लेट खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए. अगर वे अनपढ़ रहेंगे तो चाहे लालू हों या नीतीश, कोई उन्हें डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बना पाएगा. वे मजदूर ही बन पाएंगे. इसलिए जन सुराज का नारा भी है- बिहार ने कर ली तैयारी, अपने बच्चों की है तैयारी.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी का 22.67 प्रतिशत हिस्सा पहली से पांचवीं क्लास तक ही पढ़ सका है, वहीं 32 प्रतिशत ने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है. 2023 में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक बिहार की साक्षरता दर मात्र 61.8 प्रतिशत है. इसी तरह नेशनल सर्विस करियर (एनसीएस) के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 9.2 लाख है.

जाति-जमात की क्या है योजना

बिहार में जहां हर बात जाति से शुरू होती है, वहां लोग क्या इससे इतर पीके की बातों पर यकीन करेंगे. वाकई, यह एक यक्ष प्रश्न है. इसका अंदाजा उन्हें भी है. इसलिए तो उन्होंने दलित समाज के रिटायर्ड आइएफएस (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया और साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी के झंडे में महात्मा गांधी के साथ बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का चित्र भी होगा. इससे पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ-साफ कहा था कि जाति एक सच्चाई है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता. हर समाज में योग्य लोग हैं और वे किसी न किसी जाति के हैं. लेकिन जन सुराज में किसी भी स्तर पर केवल जाति ही नहीं, काबिलियत का भी ख्याल रखा जाएगा.

मोटे तौर पर समाज को पांच वर्गों में देखा जाता है- पहला सामान्य, दूसरा ओबीसी (अन्य पिछड़ा), तीसरा ईबीसी (अति पिछड़ा), चौथा अनुसूचित जाति (एससी) और पांचवां मुस्लिम समाज. किसी भी पद पर पहली बार कौन नेतृत्व करेगा, इसका भी फॉर्मूला तय किया गया है. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर जो सबसे पीछे है, उस समाज के व्यक्ति को सबसे पहला मौका मिलेगा. यह सब जन सुराज के संविधान में दर्ज किया जा रहा है. प्रशांत किशोर बिहार के ऐसे पहले नेता हैं, जो शराबबंदी हटाने और उसे चुनाव का एजेंडा बनाने की बात कह रहे. राज्य में शराबबंदी की घोषणा के बाद दो आम चुनाव तथा एक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कोई इसे हटाने की बात कहने का साहस नहीं कर सका. हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसके लागू किए जाने के तरीके पर एतराज करते रहे, यह कहते रहे कि इससे गरीब-गुरबा परेशान है, वही जेल जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी इसे हटाने की बात कभी नहीं कही.

जन सुराज का मानना रहा है कि इस पर लगे उत्पाद शुल्क से मिले राजस्व का इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर किया जा सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक अप्रैल, 2016 को राज्य में शराबबंदी लागू होने के पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य को शराब से 3,141 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था जो उसके अगले वित्तीय वर्ष में घट कर महज 29 करोड़ रह गया. अब हाल यह है कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार उत्पाद विभाग पर 600 करोड़ खर्च कर रही है.

प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार का अगला चुनाव थ्री-एस, यानि शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर पर लड़ा जाएगा. हाल ही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है. जमीन हकीकत है कि उसकी होम डिलीवरी हो रही है. एक घातक समानांतर अर्थतंत्र खड़ा हो गया है. वहीं, उनका कहना है कि जमीन सर्वे से गांवों में झगड़े हो रहे हैं. कागजात जुटाने के नाम पर लोग परेशान हैं. सर्वे के वर्तमान प्रावधान से परिवारों में विद्रोह शुरू हो गया है. आरजेडी और कांग्रेस की तरह पीके भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं. उनका कहना है कि बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी से लोगों में धारणा बन गई है कि इस मीटर के जरिए उनके बिलों से छेड़छाड़ की जा रही है. उनका मानना है कि ये सब नीतीश कुमार की पार्टी के लिए हार का कारण बनेगा.

कितना लाभकारी होगा राइट टू रिकॉल

जन सुराज के पार्टी में परिणत होने से पहले प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी वैसे ही प्रत्याशियों को टिकट देगी जो राइट टू रिकॉल (जनप्रतिनिधि को वापस करने) पर सहमति का हलफनामा देंगे. ताकि, अगर कोई उम्मीदवार जीत गया, लेकिन जनता उससे नाराज है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाए. उनका कहना था कि देश में पहली बार किसी पार्टी के संविधान में इसे लिखा जाएगा.

सत्ता की राह कितनी आसान

प्रशांत किशोर के चुनावी एजेंडे को देखा जाए तो साफ है कि शिक्षा, रोजगार और शराबबंदी उनकी प्राथमिकता में है. इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, रोजगार नहीं मिलने पर वह मजबूर होकर बिहार से पलायन कर जाता है. इसकी भयावहता पूरी दुनिया कोविड काल में देख चुकी है. पत्रकार एसके पांडेय कहते हैं, सभी दलों का अपना-अपना वोट बैंक है, जो चक्रव्यूह की तरह ही है. सबसे पहले उसे तोड़ना होगा. एक दलित को आगे कर उन्होंने इसकी शुरुआत कर भी दी है. मुस्लिम फैक्टर भी अहम है. फिर जिस शराबबंदी की वे खिलाफत कर रहे, उसके समर्थन में एक पूरी लॉबी है, जिसकी जेब में अवैध धन जा रहा है और यह सबको पता है. यह लॉबी उन्हें हर हाल में रोकेगी. लालू यादव के बाद अब नीतीश कुमार को देखते हुए भी काफी अरसा बीत गया. इसमें कोई दो राय नहीं कि विकल्प मिलने पर लोग बदलाव चाहेंगे. प्रशांत किशोर के दावे भले ही बड़े-बड़े लग रहे हों, लेकिन जो मुद्दे वे उठा रहे, वे समीचीन तो हैं. लोगों ने उन पर कितना भरोसा किया, इसकी पहली झलक नवंबर में होने वाले रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव में दिख ही जाएगी.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान

अजय कुमार

यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच उपचुनावों को लेकर चल रही वार्ता में खटास बढ़ती जा रही है। आने वाले उपचुनावों में 10 सीटों पर चुनाव होना है, और दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर असहमति नजर आ रही है। कांग्रेस, जो इस बार 5 सीटें मांग रही है, सपा के साथ एक ठोस गठबंधन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं, सपा सिर्फ 1 से 2 सीटें देने पर ही सहमत है। कांग्रेस की मांग की गई सीटों में मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर शामिल हैं। हालांकि, सपा इस मांग को लेकर साफ स्थिति में नहीं है, जिससे दोनों दलों के बीच बातचीत और अधिक जटिल हो गई है। इस स्थिति को भांपते हुए, कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जो संबंधित सीटों पर सम्मेलन कर रहे हैं। इन सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह दृष्टिकोण 50-50 फॉर्मूले पर आधारित है। पार्टी का मानना है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 5 सीटें पिछली बार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीती थीं और उन पर सपा का प्रभाव कम है। इसलिए, कांग्रेस का तर्क है कि उन्हें एनडीए वाली सीटें मिलनी चाहिए, जबकि सपा को अपनी पुरानी 5 सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एक तरह का प्रयोग है, जिससे कांग्रेस आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है। अगर कांग्रेस इस बार 5 सीटें हासिल करने में सफल रहती है, तो इसका असर भविष्य के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में कहा था कि पार्टी केवल उन सीटों पर बात करना चाहती है जहां पिछले चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों को जीत मिली थी। उनके अनुसार, जिन सीटों पर सपा ने सफलता पाई थी, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सपा का साथ देंगे, जबकि भाजपा के मजबूत क्षेत्रों में वे खुद मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यह स्थिति सपा के लिए असहज हो रही है, क्योंकि यदि वे कांग्रेस को अधिक सीटें देती हैं, तो इसका मतलब होगा कि वे अपने जनाधार को कम कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसे दो लड़कों की जोड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस चुनाव में सपा ने 298 सीटों पर और कांग्रेस ने 105 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों दलों ने साथ में चुनाव लड़ा, जिसमें सपा ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। हालांकि, अब सपा एक बार फिर से वैसी ही स्थिति में जाने से बचना चाहती है, जहां उन्हें कांग्रेस को अधिक सीटें देने की मजबूरी झेलनी पड़े। इसके बजाय, सपा अधिकतम 1-2 सीटें देने का पक्षधर है, ताकि उनकी खुद की स्थिति मजबूत बनी रहे। कांग्रेस इस बार समर्पण के साथ अपने लिए अधिक सीटें मांग रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह भविष्य की चुनावी राजनीति में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए गंभीर है।

हुड्डा का राजनीतिक भविष्य लगा दाँव पर

नीरज कुमार दुबे

चुनावों के दौरान किसी एक परिवार या एक नेता को ही सारा दारोमदार सौंपना कितना भारी पड़ सकता है, हरियाणा इसकी मिसाल बन सकता है। हरियाणा में भाजपा सरकार के खिलाफ उपजी नाराजगी का फायदा उठाने में कांग्रेस नाकाम होती दिख रही है क्योंकि उसने यहां एकजुट होकर नहीं बल्कि खेमों में बंट कर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का सारा जिम्मा जिस तरह भूपिंदर सिंह हुड्डा के कंधों पर डाला गया और इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए हुड्डा ने कांग्रेस के अन्य नेताओं को जिस तरह किनारे किया उसका विपरीत असर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर हो सकता है।

हम आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में जाटलैंड कहे जाने वाले रोहतक, झज्जर और सोनीपत में इस बार भूपिंदर सिंह हुड्डा की हालत पतली हो गई है। तीनों जिलों की 14 सीटों पर कांग्रेस का असर कमजोर हो रहा है। इसका बड़ा कारण भाजपा के स्टार प्रचारकों की रैली और कांग्रेस द्वारा दलित विरोधी बयानबयाजी और नौकरी बेचने की मानसिकता को माना जा रहा है। कांग्रेस रोहतक और झज्जर जिले में पहले से आधी सीट पर सिमटने जा रही है। सोनीपत जिले में कांग्रेस का बुरा हाल इसलिए है कि क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ सीटों पर निर्दलीयों का जोर है और कुछ को भाजपा ने कब्जे में कर ही लिया है। रोहतक-सोनीपत और झज्जर जिलों में अपनी सरकार व चौधर का नारा देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में अपने गढ़ रोहतक और झज्जर में फंसते और सोनीपत में हांफते हुए नजर आये।

रोहतक में अगर किलोई विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जिले की बाकी बची तीन सीटों पर भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भाजपा के स्टरा प्रचारकों की रैली काम कर गई है। रोहतक सिटी जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना होम टाउन मानते हैं वहां से भी भाजपा की सीट निकालती हुई

नजर आ रही है।

कांग्रेस प्रत्याशी की हालत पतली होती दिखाई दे रही है। पूर्व सहकारिता मंत्री और भाजपा प्रत्याशी मनीष ग्रोवर मजबूत स्थिति में आ गए हैं। 2019 में कांग्रेस ने जिन सीटों पर अपनी जमीन मजबूत की थी वहां कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले हुए कांग्रेस के इंटरनल सर्वे ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ-साथ कांग्रेस हाई कमान की नींद भी उड़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कांग्रेस के बागियों के कारण बहुत लंबे समय बाद मुकाबला एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल खरखौदा सीट पर कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, लेकिन यहां भी कांग्रेस की हालत उतनी ठीक नहीं है। सोनीपत और गोहाना में भाजपा के प्रत्याशियों ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया है। राई, गन्नौर और बरोदा में कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव मुकाबले में पसीना आ रहा है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस को त्रिकोणीय मुकाबले से बाहर कर दिया है। जाट लैंड का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले सोनीपत में वोटर्स ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को नकार दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गोहाना, बरोदा, खरखौदा और सोनीपत में जो बाजी मारी थी वह बाजी इस कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है।

रोहतक और झज्जर की आठ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भी समीकरण एकाएक बदल गए हैं। यहां भी अधिकतर सीट पर कांग्रेस की हालत खस्ता है। रोहतक जिले की कलानौर और महम विधानसभा सीट पर चल रही टफ लड़ाई में कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहे हैं। इसका एक कारण कांग्रेस नेताओं द्वारा जनता के बीच में नहीं रहना और जनता के काम नहीं करना है।

राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यदि रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक या दो सीटों पर निपट गए तो उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर ग्रहण लग जाएगा। झज्जर और बादली में कांग्रेस प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे ही बहादुरगढ़ और बेरी में टफ मुकाबला है। लोगों ने कहा कि इस बार झज्जर में कांग्रेस हाफ हो सकती है, इसलिए झज्जर जिले की चारों सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी को जीटी रोड बेल्ट छोड़कर बहादुरगढ़ में रोड शो करना पड़ा।

चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर में घिरते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोहाना रैली और भाजपा के अन्य दिग्गजों की रैलियों ने जाट लैंड कहे जाने वाले सोनीपत, रोहतक और झज्जर के सियासी व जातीय समीकरणों को तोड़ने का काम किया।

भाजपा ने कांग्रेस राज में दलितों पर आत्याचार के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। इसका असर चुनाव परिणाम पर दिखेगा। भाजपा ने कांग्रेस को पर्ची व खर्ची व भ्रष्टाचार पर भी घेरा। इन सवालों का जवाब देने में कांग्रेस असफल रही। जिससे जाट लैंड में हवा कांग्रेस के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है।

नई ऊंचाई पर अंतरिक्ष का निजीकरण

अभिषेक कुमार सिंह

अंतरिक्ष यूं तो मानव सभ्यता के आरंभ से ही हरेक इंसान को लुभाता रहा है, रोमन और इंका सभ्यताओं के कई रेखांकन इसकी पुष्टि करते हैं। इस ब्रह्मांड में अकेले होने की पीड़ा से ग्रस्त मनुष्य अंतरिक्ष से किसी संदेश की प्रतीक्षा में है। यही नहीं, वह खुद अंतरिक्ष के आंगन में उतरकर देख लेना चाहता है कि आखिर वहां क्या है। क्या वहां जीवन है, क्या वहां कोई और सभ्यता है। इन सवालों के हल के लिए दशकों तक जो खोजबीन हुई है, वह सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों की बदौलत हुई।

अंतरिक्ष में उनके भेजे अभियानों में उन वैज्ञानिकों और अंतरिक्षयात्रियों को मौका मिला, जो उन्हीं से जुड़े हुए थे। लेकिन हाल के दशक में अंतरिक्ष के सरकारी होने का मिथक टूटा है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और बोइंग आदि कई कंपनियों ने नासा आदि सरकारी कंपनियों का कई मामलों में सहयोग किया है। साथ ही, इन कंपनियों के भेजे स्पेसक्राफ्ट से आम इंसानों ने अंतरिक्ष की यात्रा की है। ताजा उपलब्धि आम इंसानों की अंतरिक्ष में चहलकदमी या स्पेसवॉक की है।

ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ है जब न सिर्फ निजी कंपनियों ने किसी सरकारी अंतरिक्ष कंपनी के स्पेस मिशन में सहयोग किया, बल्कि उस पर भेजे गए आम इंसानों ने अंतरिक्ष में वे प्रयोग और परीक्षण भी किए जो अब से पहले सिर्फ सरकारी अंतरिक्ष कंपनियों के वैज्ञानिक, इंजीनियर या क्रू मेंबर्स कर पाते थे। हाल में, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चार आम इंसानों को पांच दिवसीय पोलारिस डॉन मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा।

दस सितंबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुए इस मिशन को ट्विटर (एक्स) और टेस्ला के मालिक एलन मस्क और एक अन्य अरबपति जारेड आइसैनमैन ने धन और संसाधन मुहैया कराए थे। मस्क की कंपनी ने अपनी ओर से निजी विमानन कंपनी बोइंग की मदद से स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर तैयार करवाया था। इस यान से खुद जारेड आइसैकमैन (मिशन कमांडर) के अलावा तीन अन्य आम इंसान- स्कॉट 'किड' पोटीट (पायलट), साराह गिलिस और अन्ना मेनन अंतरिक्ष में पहली बार सबसे ज्यादा ऊंचाई ङ्क पृथ्वी से 1400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा (ऑर्बिट) तक गए थे। सन्? 1966 के नासा के मिशन जेमिनी-11 ने अंतरिक्ष में 1373 किमी (853 मील) की ऊंचाई तक जाने का जो कीर्तिमान बनाया था, उसे ताजा पोलारिस डॉन मिशन ने तोड़ दिया।

यह मिशन 1400 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा और इसके अंतरिक्ष यात्रियों ने थोड़ा नीचे आकर 12 सितंबर 2024 को 737 किमी की ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर

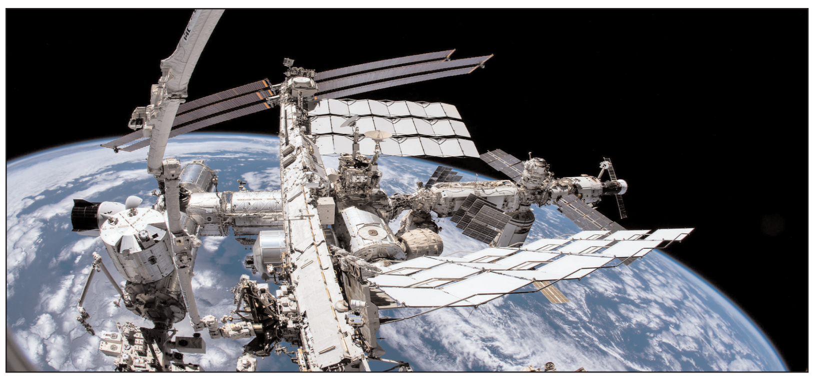

अंतरिक्ष में चहलकदमी (स्पेसवॉक) भी की। इस तरह पोलारिस डॉन की उड़ान चांद पर इंसान को ले जाने वाले अपोलो मिशनों के बाद से किसी भी इंसान द्वारा की गई सबसे ऊंची उड़ान साबित हुई है। यही नहीं, इन अंतरिक्षयात्रियों ने 31 अलग-अलग संस्थानों के साथ मिलकर इस दौरान वहां इंसानी सेहत से जुड़े 36 किस्म के शोध और प्रयोग भी किए। इस तरह अंतरिक्ष की एक निजी उड़ान सभ्यता के इतिहास में इस रूप में दर्ज हो गई है कि अंतरिक्ष से जुड़े किसी सरकारी अभियान से बाहर किसी निजी मिशन पर अंतरिक्ष यात्री न सिर्फ स्पेस में सबसे ऊपर तक गए, बल्कि वहां ठीक उसी तरह प्रयोग और परीक्षण किए- जैसे वैज्ञानिक करते हैं।

इस तरह अंतरिक्ष के निजीकरण में एक नया आयाम जुड़ रहा है। इस आयाम में निजी कंपनियां सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ जटिल अंतरिक्ष अभियानों में अपना सक्रिय योगदान और आर्थिक सहयोग दे रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष में आम इंसानों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं। हालांकि यह सही है कि अभी अंतरिक्ष में जाने वाले आम नागरिक बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एलन मस्क ने 10 लाख इंसानों को अगले एक दशक में मंगल तक ले जाने का सपना देखा है, उसके मद्देनजर ये अभियान नींव का पत्थर साबित हो सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि स्पेसएक्स और बोइंग जैसी कंपनियां अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी- नासा के कई बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में भागीदारी कर रही हैं। स्पेसएक्स ने नासा ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी योगदान दिया है। इसी वर्ष मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टअप स्पेस मशीन्स कंपनी के उपग्रह- ऑप्टिमस को स्पेसएक्स के प्रक्षेपण यान फॉल्कन-9 की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। इस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के अभियान की पृष्ठभूमि में एक भारतीय उद्यम- अनंत टेक्नोलॉजीज का योगदान भी है क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के शोध एवं अनुसंधान का काम यहां किया था। इसका उल्लेख ऑप्टिमस के प्रक्षेपण के बाद ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की उपलब्धि के बखान के रूप में किया था। विदेशों में, खास तौर से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में तो निजी कंपनियों के योगदान का रास्ता काफी पहले खुल चुका है, पर ऐसी ही एक शुरुआत हमारे देश में भी इसरो जैसे प्रतिष्ठित संगठन में भी हो चुकी है। भारत में अंतरिक्षीय कार्यक्रमों के निजीकरण का यह सिलसिला एक मिशन 'प्रारंभ' के साथ शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत हैदराबाद का एक अंतरिक्ष स्टार्टअप- स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-एस का सफल प्रक्षेपण दो साल पहले 18 नवंबर 2022 को इसरो की सहायता से कर चुका है। इसरो से इतर अन्य सरकारी संगठनों में भी कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशने की प्रेरणा जगी है जहां संस्थाओं का खर्च घटाने, कमाई बढ़ाने और निजी संगठनों को सक्रिय भागीदारी करने का मौका मिल सकता है।

जहां तक अंतरिक्ष अनुसंधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों के योगदान की बात है, तो निजी कंपनियों के प्रयासों से लग रहा है कि अंतरिक्ष एक बार फिर इंसान के सपनों की नई मंजिल बन गया है। एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की ओर की जा रही पहलकदमियां नई जरूर हैं, पर इस बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष की सैर और उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी की पहल अरसे से की जा रही है।

जैसे, चार साल पहले (30 मई 2020) एक निजी उड़ान की मदद से ही दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पहुंचे थे। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की एक साथ नागरिकता रखने वाले अरबपति एलन मस्क की कंपनी- स्पेसएक्स दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई थी, जो अपने रॉकेट से दो अंतरिक्षयात्रियों को आईएसएस तक सफलतापूर्वक ले गई थी।

टमाटर की उन्नत कृषि कार्यमाला

टमाटर अत्यंत ही लोकप्रिय तथा पोषक तत्वों से युक्त फलदार सब्जी है। जिसका उपयोग साल भर किया जाता है। सब्जी के अलावा उससे सूप, चटनी, सलाद, आदि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विटामिन व अन्य खाद्य पदार्थ उपयुक्त मात्रा में पाये जाते हैं।

भूमि- टमाटर की खेती कई किस्मों की मिट्टी में की जाती है लेकिन अच्छी जल निकासी चिकनी मृदा तथा दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है।

खेत की तैयारी :- प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाना चाहिए ताकि भूमि की निचली कठोर परत टूट जाए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए।

उन्नतशील किस्में :- पूसा रूबी, पन्त टी-1 पंजाब छुआरा, अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि।

बीज दर:- देशी - 400-500 ग्राम/ हेक्टेयर संकर - 100 ग्राम / हेक्टेयर

पौध तैयार करना (नर्सरी):- वर्षा ऋतु में 10 सें.मी. ऊंची क्यारी तैयार कर उसमें बीज बोना चाहिए। बीज कतारों में बोना चाहिए।

बीजोपचार :- बीज को बोने से पूर्व थायरम या बाविस्टिन से 2 ग्राम/ किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

बुआई का समय :- खरीफ- जून-जुलाई, शीत -अक्टूबर- नवम्बर

रोपण :- क्यारियों में जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं या 7 से 10 सें.मी. के हो जाएं तब खेत में रोपित करना चाहिए। पौध रोपण के पश्चात् तुरन्त हल्की सिंचाई करनी चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधा लगाएं।

पौध अन्तरण:- कतार से कतार की दूरी 75 सें.मी. एवं पौध से पौध की दूरी 60 सें.मी. रखना चाहिए।

उर्वरक की मात्रा :- गोबर खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। यूरिया 217 किलो प्रति हेक्टेयर, तीन भागों में देना चाहिए। पहला भाग, पौध रोपण के समय तथा दूसरा भाग एवं तीसरा भाग 30 दिन के अन्तर से देना चाहिए। एस.एस.पी. 500 किलो/ हेक्टेयर व पोटाश 100 किलो प्रति हेक्टेयर पौध रोपण के समय देना चाहिए।

सिंचाई :- टमाटर में अधिक तथा कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक हैं। शरद ऋतु में 10 से 12 दिन के अन्तर तथा गर्मी में 4-5 दिन के अन्तर में भूमि के अनुसार सिंचाई की जा सकती है।

निंदाई गुड़ाई :- टमाटर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए निरंतर निंदाई-गुड़ाई करते रहना आवश्यक है। गुड़ाई उथली करनी चाहिए जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे। 30-40 दिन बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए।

वृद्धि नियामकों का प्रयोग :- वृद्धि नियामकों का प्रयोग फूलों को झड़ने से रोकने तथा बिना निषेचन के फलों को विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। पी.सी.पी.ए. 50-100 पी. पी. एम. (50-100 मि.ग्रा./ लीटर पानी में घोलना है) के घोल का छिड़काव लाभकारी होता है।

सहारा देना :- ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाली किस्मों को पेड़ की टहनियां (बांस) की सहायता से सहारा देना चाहिए, ऐसा करने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, वर्षा ऋतु में फल तथा पेड़ सड़ते नहीं हैं। फलों का आकार बढ़ जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है।

फलों की तुड़ाई :- टमाटर के फसल की तुड़ाई कई अवस्थाओं में की जाती है-

कच्चे या हरे फल :- टमाटर को अधपके हरे से गुलाबी पड़ने पर तब तोड़ा जाता है जब इसे दूर स्थित बाजारों में विपणन हेतु भेजना होता है।

गुलाबी या हल्के लाल फल:- टमाटर को गुलाबी या हल्के लाल होने की अवस्था में तब तोड़ा जाता है जब इसे स्थानीय बाजारों में भेजना होता है।

पके हुए टमाटर :- फलों का अधिकतम भाग लाल होता है व नरम होता है ऐसे फल घरेलू उपयोग या कच्चे सलाद खाने के काम आते हैं।

अधिक पके टमाटर :- बीज उत्पादन के लिए लाल फल आदर्श माने जाते हैं। फल परीरक्षण के लिए भी अधिक पके टमाटर अच्छे माने जाते हैं।

गोभीवर्गीय में पोषक तत्वों की आवश्यकता

भूरापन या ब्राउनिंग - यह समस्या गोभीवर्गीय फसलों में बोरान की कमी से होता है।

लक्षण - भूरापन में शुरूआत में फूल में जल अवशोषित धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बड़े हो जाते हैं। इसके बाद तने में भी जल अवशोषित धब्बे पड़ते हैं तथा तना अंदर से खोखला हो जाता है। यदि भूरापन का प्रकोप ज्यादा होता है तो पूरा फूल में कुछ दिन बाद गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।

उपचार - बोरान की कमी को दूर करने के लिये 10-15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टर भूमि में पौध रोपण के समय देना चाहिए अथवा जब फसल खड़ी हो 0.1 प्रतिशत बोरेक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए प्रथम छिड़काव पौध रोपण के दो सप्ताह पश्चात और दूसरा छिड़काव फूल बनने से दो सप्ताह पहले करना चाहिए।

व्हिपटेल - यह लक्षण गोभीवर्गीय फसलों में मालीब्डिनम नामक तत्व की कमी के कारण होता है।

लक्षण - मुख्यत: मालीब्डिनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है अर्थात् मालीब्डिनम अनुपलब्ध रूप से हो जाता है, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते और व्हिपटेल के लक्षण दिखाई देते है, इसमें शुरूआत में पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियाँ सिकुड़ कर सफेद पड़ने लगती हैं तथा कुछ दिन बाद पत्तियां अपना आकार खो देती हैं और मिडरिब के अलावा शेष भाग सूख जाता है, जिसके कारण इसे सामान्यत: व्हिपटेल कहा जाता है।

उपचार - मालीब्डिनम की कमी को दूर करने के लिए अम्लीयता कम करने के उद्देश्य से 50-70 क्विंटल बुझा चूना प्रति हेक्टर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौध रोपण के पहले 2.5 से 5 किलो सोडियम मालीब्डेट प्रति हेक्टर भूमि में मिला देना चाहिए अथवा खड़ी फसल में 0.05ज सोडियम मालीब्डिेट घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए।

बटनिंग - बटनिंग की समस्या गोभी वर्गीय फसलों के कई कारणों से होती है जैसे अधिक उम्र के रोप के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण या समय के अनुसार उचित किस्मों को ना लगाने से ऐसा होता है।

लक्षण - फूलों का विकसित ना होकर छोटा रह जाना बटनिंग कहलाता है। इसमें फूलों का आकार छोटा हो जाता है तथा कम विकसित पत्तियाँ होती हैं।

उपचार - बटनिंग को रोकने के लिये अगेती या पिछेती किस्में अनुशंसित समय पर ही लगाएं, पौधे की वृद्धि चाहे वह नर्सरी में हो या खेत में नहीं रूकनी चाहिए। अधिक सिंचाई न करें। जो पौधा नर्सरी में अधिक दिन के हो उन्हें खेत में न लगाएं और नाइट्रोजन की उचित मात्रा पौधों को समय-समय पर दें।

रेसीयनेस - रेसीयनेस के लक्षण मुख्यत: वातावरण में अनुकूल तापमान की कमी, अधिक नाइट्रोजन देने के कारण तथा अधिक आर्द्रता के कारण होती हैं।

लक्षण - समय से पूर्व अविकसित कली को रेसीयनेस कहते हैं। इसमें फूल की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है तथा सफेद छोटी कलिका बन जाती है।

उपचार - रेसीयनेस से उपचार के लिये उचित किस्म का चयन करें, समय पर पौधों की रोपाई करें, नाइट्रोजन की उचित मात्रा का प्रयोग करें तथा प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।

अन्धता - अन्धता गोभीवर्गीय फसलों से पौधे की वृद्धि के शुरूआत मुख्य कलिका में कीट के प्रकोप के कारण तथा वातावरण में तापमान में कमी होने वाला पाला पड़ने के कारण होता है।

लक्षण - अन्धता में पौधे की मुख्य कलिका कीट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा इसके पत्ते बड़े, चमड़े जैसे मोटे और गहरे रंग के हो जाते हैं।

उपचार - अन्धता की रोकथाम के लिए मुख्य कलिका को कीटों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, उचित किस्म का चयन करना चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

आप सांसद अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास पर मारे गये छापे

लुधियाना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जालंधर में आप के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। संघीय जांच एजेंसी की कार्रवाई की जानकारी आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर साझा की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के आवास पर सोमवार सुबह छापेमारी शुरू की। ईडी के सूत्र ने बताया कि हैम्पटन होम्स कॉलोनी में अरोड़ा के आवास पर छापेमारी उस जमीन के एक हिस्से के संबंध में थी जो उन्हें कुछ साल पहले पंजाब सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। सूत्र ने कहा, यह जमीन एक औद्योगिक परियोजना के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन समझौते का उल्लंघन किया गया और जमीन का इस्तेमाल एक आवासीय परियोजना के लिए किया गया।

लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जमानत दी

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू और तेजस्वी यादव को काफी बड़ी राहत दी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी और कहा कि मामले की जाँच के दौरान उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने तीनों को जमानत देते हुए कहा कि मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने रखी मांग

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार झारखंड वासियों का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये लौटाना शुरू करे. झारखंड सरकार बिना शर्त 18 से 50 वर्ष तक की उम्र की हर झारखंडी बहन को इसी माह से 2500 रुपये की किस्त भेजना शुरू कर देगी. हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिख कर कहा है कि कितनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2100 रुपये देने की बात करने वाले ओडिशा में मात्र 830 रुपये महीना दे रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में हर परिवार की एक महिला को ही मां योजना का लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में शर्तों सहित 1000 रुपये दिये जा रहे हैं. सोरेन ने लिखा है कि पूरे देश में यह योजना समय की जरूरत है.प्रधानमंत्री देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2500 रुपये भेजने की योजना भी जल्द लागू करें. वरना झूठों का जुमला फेंक बहनों के बीच भेद करना बंद करें.

एयर शो की भीड़ में पांच लोगों की मौत का आरोप

चेन्नई। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुप्रतीक्षित एयर शो रविवार को समाप्त हो गया। विपक्षी दलों और मीडिया के अनुसार मरीना बीच के सामने भीड़ में फंस गए पांच लोगों की दम घुटने और बेहोशी के कारण मौत हो गई है। लेकिन पुलिस और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, जिसमें कहा गया कि कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विपक्षी पार्टी के बयानों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर शो के लिए समुद्र तट पर उमड़ी 15 लाख लोगों की भारी भीड़ में फंस गए पांच लोग बेहोश हो गए और उनका दम घुट गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मा.सुब्रमण्यम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कार्यक्रम के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और सरकार की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती गई। उनके एक पन्ने के बयान में और संपर्क करने पर किसी के हताहत होने का कोई जिक्र नहीं किया गया। सूत्रों ने यह भी कहा कि मौतों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

तेलंगाना सरकार ने किसानों को ऋण माफी का पूरा किया वादा

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया है कि उनकी सरकार ने राज्य में किसानों का कर्ज माफ करने की अपनी प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने रविवार रात प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र में कहा कि 27 दिनों की अवधि के भीतर, तेलंगाना सरकार ने 17 हजार 869 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया है, जिससे 22.22 लाख किसानों को लाभ हुआ है। एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऋण माफी के वादे के साथ तेलंगाना में सत्ता में आई कांग्रेस अपनी बात पर खरी उतरी है। ऋण माफी को चरणों में क्रियान्वित किया गया है, सरकार ने 18 जुलाई, 2024 को 1 लाख रुपये तक के ऋण वाले 11,34,412 किसानों के खातों में 6,034.97 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इसके बाद, 30 जुलाई को 6,40,823 किसानों के ऋण खातों में 6,190.01 करोड़ रुपये जमा किए गए.

शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले-

घुसपैठियों की पक्षधर है सोरेन सरकार, झारखंड में लागू करेंगे एनआरसी

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करेगी, उन्होंने दावा किया कि सीएम सोरेन राज्य में घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता रजिस्टर बनाया जाएगा और विदेशी घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है। यह चुनाव सिर्फ किसी को सीएम बनाने या सत्तासीन करने का नहीं है, बल्कि यह झारखंड को बचाने का है। भाजपा नेता ने कहा कि हम रोटी, माटी और बेटी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के कारण क्षेत्र की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। पहले संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 44 प्रतिशत से अधिक थी। अब इसे घटाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इन घुसपैठियों से आबादी बुरी तरह प्रभावित है। शिवराज ने कहा कि झारखंड का चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने या किसी राजनीतिक दल का शासन बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रदेश को बचाने का चुनाव है। बेटी, माटी, रोटी तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की जनसांख्यिकी बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% हो गयी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी भी प्रभावित हुई है। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का पक्ष ले रही है। हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे जिसमें स्थानीय निवासियों का पंजीकरण किया जाएगा और घुसपैठियों का चयन कर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर को, भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में झारखंड के युवाओं और महिलाओं के लिए पांच प्राणजारी किया। पार्टी द्वारा घोषित पांच वादे युवा साथी, गोगो दीदी योजना, घर साकार, लक्ष्मी जौहर और सुनिश्चित रोजगार हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू को उदयपुर पैलेस दौरे पर विवाद

मेवाड़ राजपरिवार समेत भाजपा सांसद ने की आलोचना

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजस्थान दौरे पर 3 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सिटी पैलेस का भी दौरा किया। यहां उदयपुर के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के साथ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनके परिवार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

राजसमंद से बीजेपी सांसद महिमा कुमारी और उनके पति नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस मामले का कोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के दौरे पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वह विश्वराज के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ से नहीं मिलीं, जिन्हें वे परिवार का मुखिया मानते हैं। महेंद्र मेवाड़ अरविंद मेवाड़ के बड़े भाई हैं। इस परिवार का वंश महाराणा प्रताप से जुड़ा है।

विश्वराज ने कहा कि जब उन्हें और उनकी पत्नी को राष्ट्रपति के सिटी पैलेस आने की जानकारी मिली तो उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पत्र में हमने संक्षेप में कहा था कि सिटी पैलेस हमारी पारिवारिक संपत्ति है और इस पर अदालतों द्वारा स्टे लगा हुआ है। इसके अलावा संपत्ति के कुछ हिस्से के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी लंबित है। इस संपत्ति को कर विभाग और जिला अदालत द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) घोषित किया गया है। मामला हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है। पत्र में सांसद और विधायक ने मुर्मू से कार्यक्रम रद्द करने का अनुरोध किया था।

अधिकारियों को दी थी जानकारी

सांसद महिमा ने कहा कि जैसे ही उन्हें मुर्मू के दौरे के बारे में पता चला, उन्होंने राष्ट्रपति के सचिव, विशेष कार्य अधिकारी और उनके उदयपुर कार्यक्रम के प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि यह राष्ट्रपति का निजी दौरा है। महिमा कुमारी ने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि एक आम आदमी के लिए निजी दौरा ठीक है, लेकिन वह राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति के कार्यालय की गरिमा है, इसलिए सिटी पैलेस जाना उनकी गरिमा के लिए भी सही नहीं है।

महिमा कुमारी ने कहा कि उन्होंने डीएम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करना पड़ा और उसके बाद कलेक्टर ने वापस फोन किया। जब मैंने डीएम से बात की तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने अधिकारियों को सही रिपोर्ट नहीं भेजी।

ओवैसी ने संघ को ही बता दिया हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा

नई दिल्ली. देश में आजकल धार्मिक आधार पर एकजुट होने के आह्वान खूब किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हिंदुओं से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा था कि बंटेंगे तो कटेंगे। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। लेकिन उनकी यह टिप्पणी एआईएमआईएम प्रमुख असदुदीन ओवैसी को चुभ गयी है। उन्होंने कहा है कि भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है ना ही मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। ओवैसी ने कहा है कि दरअसल लोगों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से ही खतरा है। हम

आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गत सप्ताह अपने राजस्थान प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां प्राचीन काल से रह रहे हैं. भले ही हिंदू शब्द बाद में आया। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू सभी को गले लगाते हैं। वे निरंतर संवाद के माध्यम से समरसता के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को दूर कर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। वहीं ओवैसी के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि चीन से भारत को खतरा है, लेकिन मोहन भागवत उसकी बात नहीं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने साथ ही वक्फ विधेयक को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारे देश में 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाह हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मैं कहता रहा हूँ कि वक्फ विधेयक लाकर ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं।

भारत पहुंचते ही बदले मोहम्मद मुइज्जू के सुर, चीन को लेकर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को दिल्ली पहुंचे. भारत की जमीन पर उतरने के बाद मुइज्जू ने आश्वासन दिया है कि उनका देश कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो. मुइज्जू की सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और नई दिल्ली के साथ अपने देश के संबंधों को पुन: स्थापित करने के लिए वे पहुंचे हैं. मालदीव और भारत के बीच संबंध उस वक्त से तनावपूर्ण हो गए जब से भारतीय सैनिकों को द्वीप राष्ट्र से वापस जाने के लिए कहा गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया. चीनी प्रशासन के करीबी

माने जाने वाले मुइज्जू ने कहा है कि चीन के साथ देश के संबंधों से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया. इसमें उन्होने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे. भारत मालदीव का एक मूल्यवान साझेदार और मित्र है. हमारे संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं. हम विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाते हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे काम से हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से समझौता न हो. जब मोहम्मद मुइज्जू से भारतीय सैनिकों की वापसी के बारे में उनके निर्णय के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि घरेलू प्राथमिकताओं पर विचार किया जा रहा है.

खेल
प्रमुख समाचार

पंकज आडवाणी ने जीता सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब, जाडेन ओंग को 5-1 से हराया

नई दिल्ली। क्यू स्पोर्ट्स के स्टार पंकज आडवाणी ने सिंगापुर में स्थानीय दावेदार जाडेन ओंग को 5-1 से हराकर सिंगापुर ओपन का बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया। फाइनल तक के सफर में पंकज ने पूर्व आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियन डेचावत पूमचेइंग को क्वार्टर फाइनल में हराया था। फाइनल में आडवाणी ने शुरुआती दो फ्रेम जीत लिए लेकिन उसके बाद ओंग ने फ्रेम जीतकर मैच में लौटने की कोशिश की। चौथे फ्रेम में आडवाणी ने शानदार खेल दिखाया। पांचवें फ्रेम में आडवाणी ने 74-6 से जीत हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। अब अगले माह पंकज आडवाणी दोहा में अपने विश्व बिलियर्ड्स खिताब की रक्षा करेंगे।

सिंगापुर ने 182 साल पुरानी घुड़दौड़ परंपरा को कहा अलविदा

सिंगापुर। जमीन की कमी से जूझ रहे सिंगापुर ने शनिवार को घुड़दौड़ की 182 साल पुरानी ब्रिटिश युग की परंपरा को अलविदा कह दिया। क्रांजी के प्रतिष्ठित सिंगापुर टर्फ क्लब (एसटीसी) रेसकोर्स ने आवास और अन्य विकास परियोजनाओं को जगह देने के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एसटीसी के बंद होने से पहले शनिवार को आखिरी दौड़ के लिए हजारों घुड़दौड़ के शौकीन यहां पहुंचे। सिंगापुर में एसटीसी 1842 से घुड़दौड़ के शौकीनों का पसंदीदा ठिकाना रहा। एसटीसी ने अपने 182 साल के सफर को 10 दौड़ों की भव्य विदाई के साथ साथ खत्म किया। इसका समापन 1.38 मिलियन सिंगापुर डॉलर के ग्रैंड सिंगापुर गोल्ड कप से हुआ।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत और यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि हुई प्रभावी

नयी दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता प्रदान करने वाली द्विपक्षीय निवेश संधि प्रभावी हो गई है। वित्त मंत्रालय ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भारत और यूएई के बीच 13 फरवरी, 2024 को अबू धाबी में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) 31 अगस्त, 2024 से प्रभावी हो गई है। यूएई के साथ इस नए बीआईटी के लागू होने से दोनों देशों के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलती है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित पहले द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (बीआईपीपीए) 12 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गया था। भारत-यूएई बीआईटी 2024 से निवेशकों के बीच सहजता का स्तर बढ़ने और उनका विश्वास बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें न्यूनतम मानक उपचार और गैर-भेदभाव का आश्वासन दिया जाएगा.

भारत के धनकुबेरों ने सिंगापुर ऑफिसों में 130 अरब डॉलर भेजे

नई दिल्ली। भारत के अति धनाढ्यों ने कैलेंडर वर्ष 2023 के अंत तक 130 अरब डॉलर की वित्तीय परिसंपत्तियां सिंगापुर के अपने फैमिली ऑफिसों में भेज दीं। इन धनकुबेरों की वजह से भारत, सिंगापुर में इस तरह की संपत्ति भेजने वाले देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। एशिया प्रशांत में केवल चीन (400 अरब डॉलर) और इंडोनेशिया (140 अरब डॉलर) उससे आगे रहे। ये आंकड़े मैकिंजी ऐंड कंपनी के एक अध्ययन से सामने आए। पिछले महीने आई अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक हॉन्ग कॉन्ग इस मामले में चौथे स्थान पर है और उसने सिंगापुर में करीब 70 अरब डॉलर फैमिली ऑफिसों को भेजे। एशिया के बाकी देशों से सिंगापुर में कुल 370 अरब डॉलर से अधिक निवेश पहुंचा है। फैमिली ऑफिस धनाढ्यों और उद्योगपतियों की निजी संपत्तियां संभालने वाली कंपनियां होती हैं। इन्हें उनकी निजी कंपनियां भी कहा जा सकता है.

हिताची एनर्जी करेगी 2000 करोड़ का निवेश

नयी दिल्ली। हिताची एनर्जी ने भारतीय कारोबार के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश में स्थायी ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता, प्रोडक्ट रेंज और टैलेंट बेस को विस्तार करने पर लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। पिछले 75 सालों में भारत की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में योगदान देते हुए हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक से लेकर हिंदुस्तान ब्राउन बॉवेरी, एबीबी पावर ग्रिड्स, हिताची एबीबी पावर ग्रिड्स और अब हिताची एनर्जी बनने तक, इस कंपनी ने 1949 से देश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई है। अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, कंपनी एनर्जी एंड डिजिटल वर्ल्ड 75 नाम से सोमवार से दो दिन का टेक्नोलॉजी इवेंट आयोजित किया है। इसमें भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करने वाली नई तकनीकों पर चर्चा की जा रही है।

त्यौहारों के बावजूद सितंबर में वाहनों की खुदरा बिक्री 9% घटी,

नई दिल्ली। सितंबर में कुल पंजीकरण घटकर 17,23,330 इकाई रह गया, जो पिछले साल इसी महीने 18,99,192 इकाई था। यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित अधिकतर श्रेणियों में सालाना आधार पर गिरावट देखी गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष सी. एस. विग्नेश्वर ने बयान में कहा, ''गणेश चतुर्थी और ओणम जैसे त्यौहारों के बावजूद डीलरों ने बताया कि प्रदर्शन काफी हद तक स्थिर रहा है।'' उन्होंने कहा कि निकट आ रहे बड़े त्यौहारों के मद्देनजर फाडा ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माता) से वित्तीय झटके से बचने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया है। यात्री वाहनों की बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत घटकर 2,75,681 इकाई रह गई, जो एक वर्ष पूर्व इसी महीने 3,39,543 इकाई थी।

बैंक अकाउंट होल्डर की मौत के बाद अगर कोई नॉमिनी नहीं तो किसे मिलते हैं पैसे?

नई दिल्ली। आजकल बैंक में अकाउंट खोलने के दौरान ही साफ तौर पर नॉमिनी को जोड़ने के लिए कहा जाता है. बैंक में सेविंग अकाउंट हो या करेंट, ज्वाइंट या डीमैट अकाउंट... सब में नॉमिनी का नाम जुड़ा होना बेहद जरूरी होता है. बैंक वाले अकाउंट होल्डर से नॉमिनी का नाम, उनका आपस में संबंध, उम्र, पता, शिक्षा,पैन नंबर वगैरह की जानकारी लेते हैं. इसके साथ ही पुराने अकाउंट में भी नॉमिनी की नाम- पता अपडेट करने के लिए कहते हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए और खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा हो तो बैंक में जमा पैसा किसे और कैसे मिलेगा? आइए, जानते हैं कि बैंक अकाउंट खोलने या चलाने के लिए उसमें नॉमिनी का नाम होना इतना जरूरी क्यों हैं. साथ ही अगर किसी बैंक खाते के लिए नॉमिनी नहीं बनाया गया और

उस अकाउंट होल्डर की किसी कारणवश मौत हो जाए तो उसके बैंक में जमा रकम किसे दी जाएगी? इस बारे में बैंकों का क्या नियम है? वहीं, ऐसी परिस्थिति में पैसे निकालने की क्या प्रक्रिया है?

बैंकों के नियम और उसकी शर्तों के मुताबिक, अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके खाते में जमा रकम उसके नॉमिनी को दी जाती है. अगर किसी अकाउंट होल्डर ने एक से अधिक नॉमिनी बनाए हैं तो उनके बीच रकम का बराबर-बराबर बंटवारा कर दिया जाता है. हालांकि, कई बैंकों में ऐसी सुविधा भी होती है, जिसके तहत कोई अकाउंट होल्डर एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने के साथ ही यह भी बंटवारा कर सकते हैं कि उनकी मौत के बाद किस नॉमिनी को जमा रकम का कितना हिस्सा दिया जाएगा.

बैंक अकाउंट होल्डर की मौत के बाद मामला तब जटिल हो जाता है जब अकाउंट में नॉमिनी (का नाम ही नहीं जोड़ा गया हो. बैंकों के नियम के मुताबिक, अगर खाते में किसी नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा गया हो तो खाताधारक की मौत के बाद जमा रकम उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपे जाते हैं. आमतौर पर किसी भी विवाहित पुरुष के कानूनी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता होते हैं. वहीं, अविवाहित पुरुष के कानूनी वारिस के रूप में उसके माता-पिता या भाई-बहन भी जमा रकम पर दावा कर सकते हैं.

बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा होने पर अकाउंट होल्डर की जमा रकम पाने के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को काफी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है. इस पूरी प्रक्रिया में समय भी ज्यादा लगता है. अकाउंट होल्डर की मौत के बाद बैंक में नॉमिनी का नाम नहीं होने पर कानूनी उत्तराधिकारी को बैंक की ब्रांच में कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना होता है. इन डॉक्यूमेंट्स में अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी का पासपोर्ट साइड फोटोग्राफ, केवाईसी, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एनेक्सचर-ए, लेटर ऑफ इन्डेम्निटी एनेक्सचर-सी, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह शामिल होते हैं.

हमारा प्रयास नक्सली गोली की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में जुड़ें: साय

प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष पूरा करने पर दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने मुलाकात के अवसर पर प्रधानमंत्री को जनसेवा के शानदार 23 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर 2001 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 23 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी पर तेजी से किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इसके साथ ही प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी आदि उपस्थित थे। बैठक में विस्तार से अच्छी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 महीने में लगातार नक्सल-आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाही की गई। इस लड़ाई में डबल इंजन की सरकार होने का लाभ भी मिला। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दौरान बहुत से मुठभेड़ हुए जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने 194 नक्सली मार गिराए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल लगातार साहस दिखा रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके साहस को नमन करते हैं। 9 महीने के अंदर 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और

742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्हें अच्छी सुविधा प्रदान करें। पुनर्वास नीति को बेहतर करने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनेक राज्यों का दौरा किया। वे हाल ही में असम गये, वहां की पुनर्वास नीति भी देखी। हम उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली गोली की भाषा छोड़कर आत्मसर्पमण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दो दिन पहले ही हम बीजापुर गये थे वहां 70 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आये हैं जो नक्सल पीड़ित परिवारों से हैं। पहले भी नियुक्ति पत्र हमने सौंपा है। हमारी सरकार लगातार उनकी सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा भी मौजूद रहे।

बिना किसी नोटिस के महिला के घर को किया सील, कोर्ट ने आईजी को जारी की नोटिस

बिलासपुर। बिना किसी आदेश के घर को पुलिस द्वारा सील किए जाने के मामले में उच्च न्यायालय में दुर्ग की महिला द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की युगलपीठ मुख्य न्यायाधीश रमेश और न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने सोमवार को अर्जेंट सुनवाई करते हुए दुर्ग आईजी को इस मामले में तत्काल निर्णय लेने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट को की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है। याचिकाकर्ता उषा कौर ने अदालत में याचिका दायर करते हुए न्याय की मांग करते हुए दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके घर को सील कर दिया है, जिसके चलते वह और उनका परिवार बेघर हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका पति एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से लापता है। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग के समक्ष एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें घर की सील खोलने और उनके पति की खोजबीन करने की मांग की गई थी। अदालत को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि जब वे घर गए तो ताला लगा होने के कारण घर को सील कर दिया गया था।

क्या पूरे गांव को सरकार फांसी दिलाना चाहती है?: बघेल

रायपुर। कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में घटित घटना पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों लोहारीडीह कांड से मिला हुआ है. कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कांड पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो लगातार प्रेसवार्ता कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं. आज एक बार फिर भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर प्रेसवार्ता कर उस सूची को जारी किया, जिसे अब तक पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने रघुनाथ साहू हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में 167 लोगों के नाम की सूची जारी की. बघेल ने बताया कि इस सूची में जो नाम शामिल हैं उनमें- 137 साहू समाज, 20 यादव समाज, 8 आदिवासी समाज, 1 मानिकपुरी समाज और 1 पटेल समाज से हैं. बघेल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विवेचना करने में बड़ी लापरवाही बरती है. पुलिस ने मृतक रघुनाथ साहू के बेटे विनोद साहू के बयान के आधार पर ही 167 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि पूरे गांव का बयान लेना था, फिर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी को जेल में डाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि हद तो यह हो गई है कि कई ऐसे लोगों का नाम भी एफआईआर में दर्ज कर लिया गया, जो गांव में घटना के दिन थे ही नहीं. अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो गांव से बाहर है उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एफआईआर में अन्य लिखकर भी छोड़ गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कभी किसी का नाम इस घटना में जोड़ा जा सकता है. और तो और कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर किया गया है. यहां तक की मॉब लीचिंग के तहत पूरे देश में पहली एफआईआर 167 लोगों के खिलाफ इसी घटना में दर्ज की गई है. गांव वालों से यह भी पता चला है कि पुलिस ने एक-एक घर नाम दर्ज करने के लिए रजिस्टर लेकर घूमती रही है. उन्होंने एफआईआर में दर्ज नाम के आधार पर सरकार से सवाल किया है कि अब सरकार ही बताए क्या पूरे गांव को फांसी दिलाना चाहती है ? क्योंकि आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तारियां की गई है. सरकार से हमारी यही मांग है कि इस मामले में दोबारा विवेचना की जाए. जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करें, जो निर्दोष है उन्हें रिहा करे.

सदस्यता अभियान को लेकर जिले में होगी मंडलवार समीक्षा बैठक

संजय, गोमती, हर्षिता, सिसोदिया पहुंचेंगे मंडलों में

रायगढ़। रायगढ़ जिला भाजपा का सदस्यता अभियान इन दिनों पूरे जिले में उफान पर है। पार्टी के जिला से लेकर मंडल, शक्ति केन्द्र व बूथ स्तर के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के मिले लक्ष्य को लेकर जमीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ उतर चुके है,इस अभियान को लेकर जिला संयोजक विकास केडिया ने बताया कि अभियान को प्रदेश में साठ लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला एवं जिल को तीन लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है रायगढ़ जिला में अब तक साठ प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया है साथ ही अभियान में और अधिक गति प्रदान करने के लिये रायगढ़ जिले एवं चारों विधानसभा के बाद अब मंडलों की समीक्षा बैठक रही गई है, प्रदेश भाजपा द्वारा संजय श्रीवास्तव,गोमती साय,हर्षिता पाण्डेय,भरत सिंह सिसोदिया को प्रदेश द्वारा अतिथि तय किये गये है, जिसके तहत रायगढ़ विधानसभा के अन्तर्गत आने वाले रायगढ़ नगर, जुटमिल चक्रधर नगर,लोंईग, कोड़तराई एवं पुसौर मंडलों कि समीक्षा बैठक लेने भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, खरसिया विधानसभा के अन्तर्गत आने वाले खरसिया नगर, रायगढ़ पश्चिम , सुपा, जोबी, महका और चपले मंडलों कि समीक्षा बैठक लेने हर्षित पाण्डेय,लैलुंगा विधानसभा के अन्तर्गत आने वाले लैलुंगा, तमनार, संबलपुरी, राजपुर, मुकडेगा और रोड़ोपाली मंडलों कि समीक्षा बैठक लेंगे।

उप मुख्यमंत्री साव ने आवास मेला में हितग्राहियों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाबी

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और और ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मंत्री राजवाड़े ने लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ

रायपुर। महिला-बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सोमवार को सूरजपुर जिला के लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही क्षेत्र के निवासियों को आज एक बड़ी सौगात नवीन तहसील कार्यालय के रूप में मिली है, जिससे लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत के लोग राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि लटोरी में तहसील कार्यालय खुल जाने से आम नागरिकों को अब राजस्व संबंधी कामकाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवीन तहसील कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के नागरिकों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इससे राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में गति आएगी। साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होगी

पीसीसी चीफ ने लोहारीडीह घटना को लेकर मोदी को लिखा पत्र, न्याय की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीह घटना के पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। बैज ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस गंभीर घटना को दबाने और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में साहू समाज के तीन लोगों की मौत हो गई, एक की हत्या हुई, जिसे फांसी का रूप दिया गया। जिसके फलस्वरूप दूसरे व्यक्ति की उसके घर में ही जलाकर हत्या कर दी गई। तीसरे व्यक्ति की इन हत्याओं के बाद हुई पुलिस कार्यवाही में पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पिटाई से मौत हुई। पुलिस अभिरक्षा में मृत प्रशांत साहू के पुरे शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। इस घटना के बाद पुलिस ने लोहारीडीह गांव के 167 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद रखा है, जिसमें 65 महिलाएं हैं व 100 से अधिक साहू समाज के ही लोग हैं। गांव वालों एवं गांव की महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक पुलिस ने कपड़े उतार कर मारपीट किया है।

महिला के आत्महत्या करने के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में एक रेलवे कर्मचारी की पत्नी ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने फेसबुक पर लाइव आकर शहर के कुछ रसूखदारों और पड़ोसी पप्पू यादव समेत 10 लोगों पर छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा एक पोस्ट भी किया है जिसमें सभी आरोपियों का नाम शामिल है। आज पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साई मंदिर के पास की है। बता दें कि आज एसपी रजनेश सिंह ने मृतका के घर जाकर परिजनों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच की जिम्मेदारी सिविल लाइन सीएसपी को दी है। एसपी ने कहा, मृतिका ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर जो पोस्ट और वीडियो डाला है उसे गंभीरता से लिया जाएगा। आत्महत्या करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, तभी कोई सुसाइड अटेंप्ट करता है या सुसाइड करता है। आत्महत्या के पीछे की वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी, यदि कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।卐

छत्तीसगढ़ हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ

रायपुर। राज्य स्तरीय हाथकरघा वस्त्रों की भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ श्री संजय श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा प्रकोष्ठ के श्री पीयूष मिश्रा एवं श्री पहलाद शादीजा, पूर्व अध्यक्ष, पूज्यनीय सिन्धु पंचायत, शंकर नगर, रायपुर एवं अन्य गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहें। हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सिन्धु पैलेस, बीटीआई ग्राउण्ड के सामने, शंकर नगर, रायपुर में 13 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। प्रदर्शनी हाथकरघा एवं खादी वस्त्रों की खरीदी पर 20-25 प्रतिशत विशेष छूट का लाभ मिलेगा। प्रदर्शनी में कोसा एवं कॉटन क्षेत्र के सिद्धहस्त बुनकर एवं शिल्पियों के द्वारा निर्मित कोसा साड़ी ड्रेस मटेरियल, चादर, बेडशीट, लहूंगी, टॉवल, रूमाल, गमछा तथा हस्तशिल्प एवं माटीकला का अनेक कलाकृत्तियां तथा खादी ग्रामोद्योग की विभिन्न उत्पाद उपलब्ध है। प्रदर्शनी के प्राकृतिक कोसा फल का धागाकरण, करघे पर वस्त्र बुनाई एवं माटीशिल्प की विद्युत चॉक से माटी शिल्प की विभन्न उत्पादों का जीवन्त प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का समय 11 बजे रात्रि 9 बजे तक रहेगा एवं प्रवेश पूर्णत: नि:शुल्क रहेगा।.

अकाउंट होल्डर को देनी होगी जमा राशि की जानकारी: हाईकोर्ट

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई खाताधारक अपने बैंक में जमा धन राशि के संबंध में सही जानकारी नहीं देता है, तो उस राशि को आयकर के दायरे में लाया जा सकता है. यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया. डिवीजन बेंच ने आयकर अधिनियम की धारा 68 और 69ए का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि खाताधारक को बैंक में जमा राशि की सही जानकारी देना अनिवार्य है. यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह राशि आयकर के दायरे में आ सकती है. इसके अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि यदि जमा की गई राशि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर है, तो उस व्यक्ति से जमा राशि के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जानी चाहिए. यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसके नाम पर खाता दर्ज है. यह महत्वपूर्ण निर्णय दिनेश सिंह चौहान की याचिका पर सुनाया गया है, जो बैंक जमा राशि की जानकारी से संबंधित है. यह फैसला न केवल खाताधारकों के लिए, बल्कि आयकर विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है.

छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को सफल स्टार्टअप स्थापित करने के गुर सिखाए देश के प्रसिद्ध स्टार्टअप विशेषज्ञों ने

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर आधारित नवीन स्टार्टअप स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों एवं नवाचारी युवाओं को सफल स्टार्टअप के गुर सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी एवं सुभाष चन्द्र बोस इन्क्यूबेशन सेन्टर, रायपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आज यहां शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में देश के विख्यात स्टार्टअप विशेषज्ञों ने नवाचारी स्टार्टअप स्थापित करने की रणनीति, संभावनाओं, शासकीय नीतियों, स्टार्टअप स्थापित करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं एवं अनुदान तथा स्टार्टअप स्थापित करने में आने वाली कठिनाईयों एवं चुनौतियों के बारे में

प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित इन्क्यूबेशन सेन्टर्स के प्रतिनिधि, स्टार्टअप संचालक, नवीन उद्यमी तथा विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति एवं छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गिरीश चंदेल ने किया। इस अवसर पर नाबार्ड रायपुर के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, उद्योग विभाग के संयुक्त संचालक श्री संजय गजघाटे सहित देश के प्रसिद्ध स्टार्टअप विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित स्टार्टअप विशेषकर बायोटेक तथा फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा सुभाष चन्द्र बोस इन्क्यूबेशन सेन्टर द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित बायोटेक स्टार्टअप्स स्थापित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इन्क्यूबेशन सेन्टर में स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को वर्किंग स्पेस, गाइडेन्स, लैब सुविधाएं, टेस्टिंग सुविधाएं, इंटर्नशिप आदि प्रदान कर उन्हें स्टार्टअप स्थपित करने में सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि द्वारा छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को नाबर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं अनुदान के बारे में जानकारी दी गई। उद्योग विभाग के संयुक्त संचालक संजय गजघाटे द्वारा उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप स्थापना हेतु दी जाने वाली सुविधाएं, संसाधन, अनुदान आदि के बारे में जानकारी दी गई।

दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान चलाई जाएंगी 6556 स्पेशल ट्रेनें

रायपुर। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 6556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक़ हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवेद्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है ।

गौरतलब है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम एवं आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की गई है। दो महीने की अवधि के दौरान ये स्पेशल ट्रेनें 6556फेरे लगाएंगी

और बड़ी तादाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगी । पिछले वर्ष भी भारतीय रेल द्वारा बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था और इन ट्रेनों ने कुल 4,429 फेरे लगाए थे, जिनके माध्यम से लाखों की संख्या में यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई थी ।

जाहिर है कि हर साल दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि परिवारों से मिलने का भी एक अहम अवसर होते हैं। हर साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश ट्रेनोंमें दो-तीन महीने पहले से ही टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। इसी को देखते हुए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी त्योहारों के अवसर पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.